



Tejasswi Prakash
Defends Karan
Kundrra...

SHARE	
सेंसेक्स	: 75,415.35
निफ्टी	: 23,719.30
SARAFI	
सोना	: 14,770
चांदी	: 295.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

27 को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक

RANCHI : झारखंड मंत्रिपरिषद् की बैठक 27 मई (बुधवार) को आयोजित होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) की ओर से जारी सूचना के अनुसार बैठक अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। बैठक में विभिन्न विभागों के अहम प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिए जाने की संभावना है।

नहीं रहे वरिष्ठ पत्रकार राजशेखर त्रिपाठी

NEW DELHI : देश के वरिष्ठ पत्रकार राजशेखर त्रिपाठी



(53) का निधन हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। गुरुवार की रात तबीयत बिगड़ने पर उन्हें नोएडा स्थित मेठो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने शुक्रवार की सुबह अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को ही नोयडा के सेक्टर-94 में कर दिया गया। आईबीएन7 से चर्चित हुए स्व. त्रिपाठी ने गोरखपुर से पढ़ाई व पत्रकारिता की शुरूआत की थी। वे कुशल रंगमंकी व कहानीकार भी थे।

पीएम को झालमुड़ी खिलाने वाले को पाक से मिल रही धमकियां

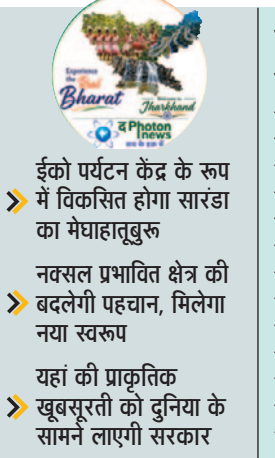
NEW DELHI : पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में झालमुड़ी बेचने वाले बिक्रम कुमार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बिक्रम की दुकान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान झालमुड़ी खरीदकर खाई थी। इस घटना के बाद बिक्रम कुमार चर्चा में आ गए थे। बिक्रम ने बताया कि उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश से फोन कॉल आ रहे हैं। कॉल करने वाले लोग उनकी दुकान उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। बिक्रम ने बताया कि एक वीडियो कॉल में कुछ लोग उन्हें हथियार भी दिखा रहे थे। इसके चलते वे और उनका परिवार काफी तनाव में है। बता दें कि पीएम मोदी ने 20 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान झाड़ग्राम में चुनावी रैली की थी। रोड शो के दौरान उन्होंने बिक्रम की दुकान से झालमुड़ी खरीदकर खाई थी।

बदलाव की बयार

छह एकड़ में बनेगा रिजॉर्ट, टूरिज्म डेवलपमेंट की तैयारी तेज, मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा -

‘बादलों के गांव वाला पहाड़’ बनेगा झारखंड का नया आकर्षण

NIKHIL KUMAR, RANCHI : कभी नवसली गतिविधियों के कारण सुखियों में रहने वाला पश्चिमी सिंहभूम का सारंडा क्षेत्र अब अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन संभावनाओं के लिए नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। सारंडा की वादियों में स्थित मेघाहातुबुरु को झारखंड सरकार बड़े ईको-पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने जा रही है। शुक्रवार को पर्यटन, कला-संस्कृति, युवा कार्य एवं खेलकूद विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने द फोटोन न्यूज के मुख्य संवाददाता से विशेष बातचीत में बताया कि मेघाहातुबुरु में छह एकड़ भूमि विकसित कर ली गई है, जहां प्रकृति के अनुरूप इको रिजॉर्ट और अन्य पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यटन ढांचा मजबूत करने और दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर सड़क



संपर्क से जोड़ने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सारंडा जैसे प्राकृतिक और जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र को राज्य के बड़े पर्यटन

नाम में ही छिपी है इस जगह की पहचान

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि मेघाहातुबुरु नाम ही इस स्थल की विशेषता को दर्शाता है। स्थानीय भाषा में 'मेघ' का अर्थ बादल, 'हातु' का मतलब गांव और 'बुरु' यानी पहाड़ होता है। अर्थात 'बादलों के गांव वाला पहाड़'। यह इलाका वर्ष के लगभग पांच महीने बादलों से ढंका रहता है। पहाड़ियों पर तैरते बादल, घने साल वन, ठंडी हवाएं और दूर-दूर तक फैली हरियाली इसे प्राकृतिक स्वर्ग जैसा अहसास देती है। पर्यटक प्रकृति को करीब से महसूस कर सकेंगे।

केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में गंभीरता से काम किया जा रहा है। सुदिव्य कुमार ने बताया कि झारखंड पर्यटन विकास निगम के

बेहद करीब से देख सकेंगे खूबसूरती

सरकार की योजना यहां प्रकृति के अनुरूप पर्यटन सुविधाएं विकसित करने की है, ताकि लोग सारंडा की खूबसूरती को बेहद करीब से महसूस कर सकें। यहां दर्शनीय स्थल, ठहरने की व्यवस्था, ऊँचाई से प्राकृतिक दृश्य देखने के स्थान और बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले वर्षों में मेघाहातुबुरु झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी अलग पहचान बनाएगा।

रेल व सड़क मार्ग दोनों की सुविधा

मेघाहातुबुरु पहुंचने के लिए रेल व सड़क मार्ग दोनों की सुविधा है। इसका नजदीकी रेलवे स्टेशन झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में पड़ने वाला बड़ाजमदा और ओडिशा के वोंडार जिला स्थित बड़बिल है। बड़ाजमदा से इसकी दूरी 24 किमी व बड़बिल से 28 किमी है। हावड़ा-बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस यहां तक पहुंचने के लिए सबसे सुविधाजनक साधन है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मुख्यालय चाईबासा से इसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर है।

माध्यम से यहां विकास कार्य कराया जाएगा। जल्द ही पर्यटकों को बेहतर ठहरने, घूमने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने की सुविधाएं उपलब्ध

कराई जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा ताकि बाहर से आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

26 सीटों के लिए ईसीआई 1 जून को जारी करेगा अधिसूचना, 18 को होगा मतदान

झारखंड सहित 12 राज्यों में राज्यसभा चुनाव का एलान

- सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग, शाम 5 बजे से शुरू होगी काउंटिंग
- 8 जून तक किया जाएगा नॉमिनेशन, 9 को होगी नामांकन पत्रों की स्कूटनी
- 11 जून तक वापस लिए जा सकते हैं नाम

PHOTON NEWS RANCHI : शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग (सीआई) ने झारखंड सहित 12 राज्यों में राज्यसभा की 26 सीटों पर चुनाव का एलान कर दिया। झारखंड की दो सीटों पर चुनाव होना है। दो सीटों पर उपचुनाव भी होना है। आयोग 1 जून से इसके लिए प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। रिटायर हो रहे सदस्यों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह, पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा समेत 24 सांसद शामिल हैं। इन सभी सीटों से मौजूदा सदस्य 21



वोटिंग के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

आयोग ने कहा कि मतपत्रों पर अपनी पसंद अंकित करने के लिए केवल रिटर्निंग अधिकारी की ओर से उपलब्ध कराए गए, पहले से तय विशिष्टताओं वाले, एकीकृत बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग करने की अनुमति होगी। किसी अन्य पेन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

जून से 19 जुलाई के बीच रिटायर हो रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक, 1 जून को अधिसूचना जारी होते ही

किस राज्य से कितने सदस्य हो रहे रिटायर

- आंध्र प्रदेश – चार
- गुजरात स- चार
- झारखंड स- दो
- मध्य प्रदेश – तीन
- मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश- एक-एक
- कर्नाटक – चार
- राजस्थान – तीन

21 जून को समाप्त हो रहा दीपक प्रकाश का कार्यकाल

राज्यसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही राजनीतिक गलियारों में सुगबुहाहट तेज हो गई है। राज्य में दो सीटों के लिए चुनाव होना है। दिवंगत शिबू सोरेन के निधन की वजह से 4 अगस्त 2025 से राज्यसभा की एक सीट खाली है, जबकि दूसरी सीट दीपक प्रकाश के 21 जून को कार्यकाल समाप्त होने की वजह से खाली हो रही है।

नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। 8 जून तक नामांकन पत्रों भरा जाएगा। 9 जून को नामांकन पत्रों की स्कूटनी

निर्वाचन आयोग की तैयारी शुरू

झारखंड में राज्यसभा के दो सीटों के लिए होनेवाले चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि आगामी 1 जून को अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 8 जून तक चलेगी। यदि दो से अधिक अभ्यर्थी चुनाव मैदान में होते हैं, तो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और इसी दिन शाम 5 बजे मतों की गिनती करा कर चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने के लिए चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन होगा।

होगी। 11 जून को नामांकन वापसी की तिथि निर्धारित की गई है। 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। वोटों की

झामुमो के खाते में एक सीट आना तय

यदि आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो राज्यसभा चुनाव में सतारुद जेएमएम कांग्रेस राजद के पास 56 विधायकों का मत है, जिसमें जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के पास 16 और राजद के 4 विधायक और भाकपा माले के 2 विधायक है।

विपक्ष की ओर से प्रत्याशी उतारने की संभावना

वहीं विपक्षी खेमे में 24 विधायकों का समर्थन है। जिसमें बीजेपी के 21, आरज्यू, लोजपा और जदयू के 1-1 विधायक शामिल हैं। पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के बावजूद विपक्ष की ओर से प्रत्याशी को उतारने की संभावना जताई जा रही है।

गिनती उसी दिन यानी 18 जून को शाम 5 बजे से शुरू की जाएगी। 20 जून तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

छत्तीसगढ़ की भाजपा नेत्री से दिल्ली में दुष्कर्मी रांची से कारोबारी अरेस्ट

BILASHPUR : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से भाजपा नेत्री के साथ दुष्कर्मी और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि झारखंड के रांची निवासी कारोबारी संजय सिंह ने दिल्ली में महिला के साथ रेप किया। बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात पहले दिल्ली में हुई थी, जहां आरोपी ने माइनिंग कारोबार में निवेश का झांसा देकर महिला से नजदीकियां बढ़ाईं। पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। शुक्रवार को बिलासपुर पुलिस ने झारखंड के रांची से आरोपी संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया है।

पाकिस्तान-बांग्लादेश की सीमाओं पर शुरू होगी 'स्मार्ट बॉर्डर' परियोजना : अमित शाह

NEW DELHI @ PTI : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार अगले साल 'स्मार्ट बॉर्डर' परियोजना शुरू करेगी ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ 6,000 किलोमीटर लंबी सीमा को अभेद्य बनाया जा सके और इन क्षेत्रों की जनसांख्यिकी को बदलने की साजिश विफल की जा सके। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा यहां आयोजित वार्षिक रुस्तमजी स्मृति व्याख्यान में शाह ने इस बात को भी दोहराया कि सरकार देश से प्रत्येक घुसपैटिए को ढूँढ निकालेगी और उन्हें भारत से बाहर भेजेगी। के.एफ. रुस्तमजी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के संस्थापक



- सरकार देश से प्रत्येक घुसपैटिए को ढूँढकर भेजेगी बाहर
- अभेद्य सीमा बनाने में प्रौद्योगिकी, ड्रोन, रडार और स्मार्ट कैमरों का किया जाएगा उपयोग

और पहले महानिदेशक थे। बीएसएफ में लगभग 2.70 लाख जवान हैं और इसे पश्चिम में

पश्चिम एशिया और होर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ने से दुनिया में तेल और ईंधन की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ रही है। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और उसके आर्थिक प्रभाव का जिक्र करते हुए मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है कि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो। सूत्रों के अनुसार, बैठक को सरकार के कामकाज की समीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य राज्य मंत्री शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल रहे।

होटवार जेल में महिला कैदी से यौन शोषण मामले में हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

PHOTON NEWS RANCHI :

बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के डीजीपी और सरकार से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। शुक्रवार को वेकेशन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए अगली सुनवाई 8 जून को निर्धारित किया।

जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की वेकेशन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट को जानकारी दी गई कि राज्य सरकार के गृह विभाग ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। इस समिति में निदेशक प्रशासन मनोज कुमार, सहायक कारा निरीक्षक आधार रंजन गुता और कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय के प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमौली सिंह को शामिल किया गया है।

यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व प्रिंसिपल को तीन साल की सजा

PHOTON NEWS RANCHI : शुक्रवार को सिविल कोर्ट ने झारखंड की राजधानी रांची स्थित डीएवी कपिलदेव पब्लिक स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा को नर्सिंग स्टाफ के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा जगत और शहर में इस मामले की चर्चा तेज हो गई है। इस मामले में अदालत ने गुरुवार को ही मनोज कुमार सिन्हा को दोषी करार दे दिया था। सुनवाई



- डीजीपी और सरकार से दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब
- जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की वेकेशन बेंच में हुई सुनवाई
- गृह विभाग ने जांच के लिए बनाई है तीन सदस्यीय कमेटी, 8 जून को होगी अगली हियरिंग

इसके अलावा झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस्पन प्रसाद के निर्देश पर रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डालसा की टीम ने मामले में पूछताछ की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायिक जांच की जा रही है। रांची जिला प्रशासन और जेल आईजी के स्तर पर अलग-अलग जांच शुरू कर दी गई है।

मई 2022 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी

मामले की शुरूआत मई 2022 में हुई थी, जब स्कूल की एक महिला कर्मी ने तत्कालीन प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा पर यौन उत्पीड़न और अश्लील मांग करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने रांची के अग्रगोदा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी।

के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों और जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी माना. इसके बाद अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने तीन साल की कैद और आर्थिक दंड का आदेश दिया।



CHAI BASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा क्षेत्र में सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश करते हुए पूर्वी और पश्चिमी पंचायत ने चार टीबी मरीजों को गोद लिया है। दोनों पंचायतों ने दो-दो मरीजों का चयन कर उन्हें पोषण आहार उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि चयनित सभी मरीजों को लगातार एक वर्ष तक पौष्टिक आहार दिया जाएगा। इससे उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो सकेगा। पंचायत स्तर से इन मरीजों के समुचित इलाज की पूरी जिम्मेदारी भी उठाई गई है। पूर्वी पंचायत की मुखिया चांदमनी लागुरी और पश्चिमी पंचायत की मुखिया पद्मिनी लागुरी ने कहा कि क्षेत्र के कमजोर और जरूरतमंद मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना ही इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण न तो पौष्टिक भोजन ले पाते हैं और न ही सही इलाज करा पाते हैं। ऐसे में पंचायत की यह पहल उनके लिए संजीवनी साबित होगी।

टोकलों में ध्वस्त की गई 5 अवैध शराब भट्टियां

CHAI BASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र में पुलिस और उत्पाद विभाग ने शुक्रवार को माली साई गांव में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान अवैध शराब की 5 भट्टियां ध्वस्त कर दी गईं, जबकि मौके से करीब 1600 किलो जावा महुआ जब्त किया गया। इसे टीम ने तत्काल नष्ट कर दिया। इसके साथ ही 40 लीटर चुलाई देसी शराब भी बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त किए गए।

बकरीद की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन



JAMSHEDPUR : बकरीद का पर्व 27 मई को मनाया जाएगा। इसे लेकर टाउन हॉल, सिद्दगोड़ा में शुक्रवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिटी एसपी, एसडीएम धालभूम, एसपी, एसडीएम घाटशिला, सभी बीडीओ, सीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी समेत शांति समिति के सदस्य भी उपस्थित थे। बैठक में पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण, संवेदनशील स्थलों पर विशेष नियरानी, यातायात प्रबंधन, साफ-सफाई, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति की निर्बाध व्यवस्था आदि को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं आपत्तिजनक पोस्ट साझा नहीं करने की अपील की गई। उपायुक्त ने कहा कि सभी लोग आपसी सौहार्द एवं भाईचारे की भावना के साथ पर्व मनाएं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल प्रशासन को सूचना दें।

77 साल में भी नहीं बने नदी-पहाड़ संरक्षण के कानून : राजेंद्र सिंह



कार्यक्रम का उद्घाटन करते राजेंद्र सिंह व विधायक सरयू राय

PHOTON NEWS JSR : तरुण भारत संघ, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद, युगांतर भारती, नेचर फाउंडेशन, स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट, जल विरादरी और मिशन के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को साकची स्थित मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के सभागार में दो दिवसीय राष्ट्रीय नदी पर्वत सम्मेलन आरंभ हुआ। इसमें पर्वत भर से विशेषज्ञ आए हैं। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नदी और

पहाड़ों के लिए एक विशिष्ट और ठोस कानून बनाना है। इस मौके पर मैससे पुरस्कार विजेता जलपुरुष राजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारों ने बीते 77 सालों में नाक-बाल काटने वाले कई कानून बनाए, जिन्हें इन्वॉयमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि हृदय और फेफड़े को न काटने वाला कानून आज तक न बना। भारतीय संविधान की आर्टिकल 21 और 41 में जीवन

को बचाने की जिम्मेदारी है। सिर्फ आदमी का नहीं, पेड़-पौधे, जीव-जंतु की रक्षा के लिए व्यवस्था है। राजेंद्र सिंह ने सवाल किया कि ब्यूरोक्रेसी, ज्यूडिशियरी, टेक्नोक्रेट्स, अधिवक्ता...ये सब क्या कर रहे हैं। उन्होंने इसका जवाब भी खुद ही दिया। कहा: जो चीजें बिगड़ रही हैं, उन्हें ये टेम्पररी सॉल्यूशन देकर चलने लायक बना दे रहे हैं। जुगाड़ कर-के चीजों को ठीक रहे हैं, ताकि जनता में उफान न आए। इसके लिए बहुतेरे कानून बनाए गए हैं। भारतीय संविधान भारतीय धरती पर रहने वालों को संरक्षण और सुरक्षा देना चाहता है, उस संविधान के इंटेंशन को लोग देख नहीं पा रहे हैं। जलपुरुष ने कहा कि पहाड़ लगातार कट रहे हैं। अरावली पर उन्होंने लड़ाई लड़ी और जीते भी।

समस्या कुलपति ने डॉ. अन्नपूर्णा झा को सौंपा प्रभारी कुलसचिव का दायित्व, लेकिन नहीं दिए गए वित्तीय अधिकार

महिला विवि की कुलसचिव ने दिया इस्तीफा, वेतन-भुगतान हुए लंबित

PHOTON NEWS JSR : जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की की प्रभारी कुलसचिव डॉ. सलोमी कुजूर 13 मई से लगभग एक महीने के अवकाश पर हैं, जिससे विवि के कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो गए हैं। उनके अवकाश पर जाने के बाद प्रशासनिक निर्णयों और वित्तीय प्रक्रियाओं में ठहराव आ गया है। परिणामस्वरूप शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन लंबित है और विविध विभागों की फाइलें कार्यालयों में लंबित पड़ी हैं। जानकारी के अनुसार डॉ. कुजूर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कुलपति की ओर से इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। उनकी अनुपस्थिति तक कुलपति ने डॉ. अन्नपूर्णा झा को प्रभारी कुलसचिव का दायित्व सौंपा



वेतन भुगतान पर महारथी संकट

रजिस्ट्रार कार्यालय में वित्तीय अनुमोदन लंबित रहने से विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान प्रभावित हो गया है। इस स्थिति से स्थायी, वोकेशनल, सविदा तथा आउटसोर्स श्रेणी के कर्मचारी प्रभावित हैं। समय पर वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों में आर्थिक संकट की स्थिति बन रही है और असंतोष बढ़ता जा रहा है।

है, लेकिन उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए हैं। गौरतलब है कि डॉ. कुजूर अक्टूबर 2025 से प्रभारी कुलसचिव के रूप में

असमंजस और असंतोष का माहौल, कर्मचारी व शिक्षक निर्णयहीनता से परेशान

प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि ऐसी स्थिति में कुलपति कार्यालय को नए प्रभारी कुलसचिव के लिए नाम प्रस्तावित कर राजभवन को भेजना चाहिए, ताकि प्रशासनिक और वित्तीय कार्य प्रभावित न हो। हालांकि अब तक प्रभावी दैनिक व्यवस्था नहीं होने से विश्वविद्यालय में असमंजस और असंतोष का माहौल बना हुआ है। कर्मचारी और शिक्षक निर्णयहीनता से परेशान हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अब तक कोई स्पष्ट आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे पारदर्शिता की कमी महसूस की जा रही है। शिक्षकों और कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासनिक अविश्वसनीयता और चर्चाएं तेज हो गई हैं।

असमंजस और असंतोष का माहौल, कर्मचारी व शिक्षक निर्णयहीनता से परेशान

प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि ऐसी स्थिति में कुलपति कार्यालय को नए प्रभारी कुलसचिव के लिए नाम प्रस्तावित कर राजभवन को भेजना चाहिए, ताकि प्रशासनिक और वित्तीय कार्य प्रभावित न हो। हालांकि अब तक प्रभावी दैनिक व्यवस्था नहीं होने से विश्वविद्यालय में असमंजस और असंतोष का माहौल बना हुआ है। कर्मचारी और शिक्षक निर्णयहीनता से परेशान हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अब तक कोई स्पष्ट आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे पारदर्शिता की कमी महसूस की जा रही है। शिक्षकों और कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासनिक अविश्वसनीयता और चर्चाएं तेज हो गई हैं।

एक टेबल से दूसरी टेबल तक घूम रही फाइलें

कर्मचारियों का आरोप है कि वेतन से जुड़ी फाइलें लगातार एक टेबल से दूसरी टेबल तक घूम रही हैं, लेकिन अंतिम निर्णय लेने के लिए कोई अधिकृत अधिकारी उपलब्ध नहीं है। प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट जिम्मेदारी तय नहीं होने के कारण समस्या और गंभीर हो गई है।

छात्रावास व्यवस्था पर गंड़राया संकट

विश्वविद्यालय के छात्रावासों में भोजन व्यवस्था संचालित करने वाले मेस वेंडरों का भुगतान लंबित होने से स्थिति गंभीर होती जा रही है। वेंडरों का कहना है कि लगातार बकाया बढ़ने के कारण खाद्य सामग्री की आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ, तो वे नियमित आपूर्ति जारी रखना मुश्किल समझेंगे। भुगतान में देरी जारी रही तो छात्रावासों की भोजन व्यवस्था बाधित हो सकती है। इसका सीधा असर छात्रों पर पड़ेगा और उन्हें दैनिक भोजन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

वर्षों से प्रभारी व्यवस्था के सहारे चल रहा विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार मौजूदा प्रशासनिक संकट का एक प्रमुख कारण स्थायी कुलसचिव की नियुक्ति का लंबित रहना है। कॉलेज से विश्वविद्यालय में उन्नयन के बाद से अब तक नियमित कुलसचिव की नियुक्ति झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से नहीं हो सकी है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 में जेपीएससी ने एक नियमित कुलसचिव का चयन भी किया था, लेकिन उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया। इसके बाद से विश्वविद्यालय लगातार प्रभारी व्यवस्था के सहारे संचालित हो रहा है।

कदमा में जुआ अड़्डा से गोरखपुर निवासी सहित आठ गिरफ्तार

बड़े पैमाने पर जुआ खेल होने की मिली थी सूचना, लोगों को बना रहे थे ठगी और धोखाधड़ी का शिकार



गिरफ्त में आरोपी व मामले की जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी

टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और जुआ खेलते हुए आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 35,520 रुपये नकद, सात मोबाइल फोन, ताश की गड्ढी और जुआ खेलने में प्रयुक्त एक दरी बरामद की है। यह सारा सामान जब्त कर लिया गया है। इस मामले में कदमा थाना प्रभारी के बयान के आधार पर कदमा थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और बंगाल जुआ अधिनियम 1867 के तहत कार्रवाई कर दी है। गिरफ्तार आरोपियों में जमशेदपुर, सोनारी,

पकड़े गए थे जुआरी

पकड़े गए लोगों में सोनारी के ग्वाला बस्ती में बबलू के मकान में किराए पर रहने वाला गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का राजन गुप्ता उर्फ राजन, सरायकेला जिले के डोबो का रहने वाला राजेश कुमार तुरहा, जमशेदपुर के कदमा भाटिया बस्ती का रहने वाला गोविंद कुमार शाह, सोनारी के पंचवटी नगर का रहने वाला दीपक कुमार उर्फ दीपू, कदमा भाटिया बस्ती का रहने वाला बंटी कुमार गुप्ता, सोनारी के पंचवटी नगर का रहने वाला लालचंद तुरहा, सोनारी के झाबरी बस्ती का रहने वाला सुखदेव सिंह और सोनारी के ही मरारपाड़ा का रहने वाला लखन कुमार ठाकुर उर्फ आजाद ठाकुर शामिल हैं।

चाईबासा से 200 आदिवासी दिल्ली के लिए हुए रवाना



चाईबासा में प्रकरों को संबोधित करते संयोजक

CHAI BASA : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लालकिला मैदान में 24 और 25 मई को दो दिवसीय जनजाति सांस्कृतिक समारोह का आयोजन होगा। इसमें शामिल होने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले से करीब 200 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को दिल्ली रवाना हुआ। चाईबासा से रवाना होने से पहले जनजाति सुरक्षा मंच के जिला संयोजक मनोज लेवांगी और सह संयोजक हरिचरण सांडिल ने प्रेसवार्ता में बताया कि आजादी के 78 साल बाद भी जनजातीय समुदाय को उनका पूरा हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा है। जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग धर्मांतरण कर दूसरे धर्म में चले गए हैं और जनजातीय परंपरा व मान्यताओं को नहीं मानते, वे भी जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोग जनजातीय समाज के अधिकार छीन रहे हैं। संयोजकों ने कहा कि संविधान में दी गई व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने के लिए दबाव बनाया जाएगा।

नियमावली के अनुसार कराएं पेसा कानून का संचालन, माझी परगना माहाल ने रखी मांग

PHOTON NEWS GHATSILA : पेसा कानून को नियमावली के अनुरूप लागू करने की मांग उपायुक्त के की गई है। इस सिलसिले में माझी परगना माहाल पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था धाड़ दिशोम, पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को उपायुक्त से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व देश परगना बाबा बैजू मुर्मू ने किया। जापन के माध्यम से पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के अगुवाओं ने मांग की कि वर्षों पुराने मांग पेसा नियमावली झारखंड प्रदेश में लागू हो गई है। धरातल पर विस्तार करने के लिए विभाग द्वारा निर्देश जारी किया जा रहा है। इसका माझी पारगना माहाल ने विरोध करते हुए नियमावली के अनुसार पेसा कानून संचालन करने का अनुरोध



उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते माझी परगना माहाल के प्रतिनिधि

किया। सर्वप्रथम उपायुक्त द्वारा प्रत्येक ग्रामसभा के अध्यक्ष को अनुसूचित जनजाति समुदाय के ऐसे व्यक्ति जो पारंपरिक रूप से माझी, पारगना, मुंडा, मानकी आदि नामों से जाना जाता हो ऐसे व्यक्ति को सत्यापन एवं प्रकाशन कर प्रमाणपत्र दिया जाए, इसके बाद ही उनकी अध्यक्षता में बैठक कर आगे का कार्य बढ़ाया जाए। इसके साथ ही आदिवासी समाज ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को विरोध पत्र भेजा।

इसमें कहा गया कि हिंदू संगठन जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा 24 मई को लाल किला मैदान गई दिल्ली में आयोजित होने वाले जनजाति संस्कृति समारोह का विरोध कर रहे हैं। जनजाति सुरक्षा मंच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अंग है, इनकी संस्था आदिवासियों को जबरन हिंदू धर्म शामिल करना है। ये लोग आदिवासियों के सरना धर्म को नहीं मानते हैं। सरना और सनातन एक है, का राग अलापते हैं।

रेलवे के सभी अस्पतालों में मिलेगी डायलिसिस व वेंटिलेटर की सुविधा



कोलकाता की बैठक में शामिल यूनियन के पदाधिकारी

CHAKRADHARPUR : दक्षिण पूर्व रेलवे की एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस यूनियन की इस वर्ष पहली जेनरल पीनएसम बैठक 21-22 मई को कोलकाता स्थित महोपबन्धक सभागार में हुई। दो दिवसीय बैठक में रेलवे कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद प्रबंधन ने कई मांगों पर सहमति जताई। इसमें तय हुआ कि दक्षिण पूर्व रेलवे के सभी मंडल अस्पतालों में आईसीयू, वेंटिलेटर और डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे अस्पतालों में नियमित और पूर्णकालिक डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए हावड़ा में रैस्ट रूम की बेहतर व्यवस्था करने पर भी सहमति बनी। रेलवे कर्मचारियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर निशुल्क शौचालय और वाहन पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। चक्रधरपुर मंडल के ट्रेन मैनेजरों के लिए हावड़ा रनिंग रूम में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जाएगी। वहीं सरदेगा स्टेशन भवन में यात्रियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए लिफ्ट लगाने का निर्णय लिया गया।



KATI HAR : जिले के मुफ्फसिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पथलबाड़ी-जाफरगंज सड़क के पास से 100 ग्राम स्मैक, दो मोबाइल और एक मोटरसाइकिल के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई 21 मई की देर रात्रि में की गई। मुफ्फसिल थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि पथलबाड़ी-जाफरगंज सड़क की ओर दो व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए थानाध्यक्ष ने पुलिस बल के साथ मौके पर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही दोनों व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें बल के सहयोग से खदेड़कर पकड़ लिया गया। पृष्ठताछ में पकड़े गए लोगों ने अपना नाम अबु सुफियान, उम्र 31 वर्ष, पिता नजरूल हक, सा० इमली टोला, थाना मनसाही, जिला कटिहार और मो. नासिम, उम्र 30 वर्ष, पिता हजरत अली, सा. सहजा, थाना मनसाही, जिला कटिहार बताया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से 100 ग्राम स्मैक, दो मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। मुफ्फसिल थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस बरामद स्मैक के स्रोत और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

गांजा व ब्राउन शुगर के साथ पकड़ाए दो तस्कर



BHAGALPUR : पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से गांजा और ब्राउन शुगर के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उक्त आशय की जानकारी शुक्रवार को सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने दी। सिटी एसपी ने बताया कि पहली कार्रवाई मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के सहजानपुर में की गई। जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 750 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नीलू देवी पति धर्मेन्द्र चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के घर से गांजा बरामद किया और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरी कार्रवाई जोगसर थाना क्षेत्र में की गई जहां बुढ़ानाथ मंदिर के समीप पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक युवक को 6.88 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजा मंडल के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री हो रही है। जिसके बाद विशेष टीम का गठन कर कार्रवाई की गई। दोनों मामलों में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों से पृष्ठताछ जारी है। सिटी एसपी ने कहा कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अवैध कारतूस के कारोबार का खुलासा, एक अरेस्ट



EAST CHAMPARAN : जिले में पुलिस ने लाइसेंसी हथियार की आड़ में चल रहे अवैध कारतूस कारोबार का बड़ा खुलासा किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर हरसिद्धि थाना की पुलिस की विशेष टीम ने प्रखंड विकास पदाधिकारी की मौजूदगी में हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मुरापुर पंचायत के औरैया गांव छापेमारी कर एक लाइसेंसधारी को भारी मात्रा में कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद कलाम के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग करते हुए नियमों के विपरीत कारतूस की खरीद-बिक्री के धंधे में शामिल था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर से लाइसेंसी हथियार के साथ बड़ी संख्या में रायफल के कारतूस बरामद किए हैं जिसके बाद पुलिस ने हथियार को भी जब्त कर मामले की गहन तहकीकात शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है, कि कारतूस कहाँ से लाकर किन लोगों को दिए जाते थे। मामले में आरोपी के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि शस्त्र अनुज्ञप्ति के नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पहल 25 मई से रोज होगी राजस्व कार्यों की समीक्षा, मंत्री दिलीप जायसवाल खुद करेंगे जिलों की मॉनिटरिंग

दाखिल-खारिज से लेकर ई-मापी तक की होगी गहन पड़ताल

● राजस्व महाअभियान की होगी सीधी मॉनिटरिंग 11 जून तक की जाएगी योजनाओं की समीक्षा

AGENCY PATNA :

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने 25 मई से 11 जून 2026 तक राज्य के सभी जिलों के राजस्व कार्यों की प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करने का निर्णय लिया है। समीक्षा की कमान खुद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल संभालेंगे। विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक कार्य दिवस में तीन जिलों की अलग-अलग सत्रों में समीक्षा की जाएगी। बैठकें तीन पालियों में होंगी। पहली पाली शाम



पत्रकारों को संबोधित करते मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल

इन बिंदुओं पर रहेगा विशेष फोकस

समीक्षा के दौरान ऑनलाइन दाखिल-खारिज के लंबित मामलों, डिफेक्ट वेक और निष्पादन की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परिमार्जन प्लस के तहत डिजिटाइज जमाबंदी के शुद्धिकरण और छूटी हुई जमाबंदियों के डिजिटाइजेशन की प्रगति भी जांची जाएगी। इसके अलावा ई-मापी, अभियान बसेरा, सरकारी भूमि सत्यापन और राजस्व महा-अभियान से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा होगी। विभाग ऑनलाइन आवेदन अपलोडिंग और एट्री की प्रगति का भी आकलन करेगा। मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि दैनिक मॉनिटरिंग व्यवस्था का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन, डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और आम लोगों को राजस्व सेवाओं का शीघ्र लाभ उपलब्ध कराना है।

चार बजे से पांच बजे तक, दूसरी पाली पांच बजे से छह बजे तक और तीसरी पाली छह बजे से सात बजे तक चलेगी। अपर सचिव

आजीव वत्सराज द्वारा जारी पत्र में सभी जिालाधिकारियों को स्वयं बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बंदोबस्त

पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों की

उपस्थिति भी अनिवार्य की गई है। विभाग ने अद्यतन प्रतिवेदन के साथ समीक्षा में शामिल होने को कहा है।

प्रेमी के साथ रहने के लिए रची खुद की हत्या की झूठी कहानी, महाराष्ट्र में मिली

मुर्गा काटकर घर में छींट दिया था खून, उसी रात हो गई फरार, परेशान रही पुलिस

PHOTON NEWS SASARAM :

रोहतास में प्रेम प्रसंग में एक नाबालिग लड़की ने एक ऐसी कहानी रची कि घर वाले ही नहीं, पुलिस भी 15 दिनों तक परेशान रही। इंदपुरी इलाके के एक गांव की 16 वर्षीय लड़की ने अपने ही घर में एक मुर्गा काटकर उसके खून को पूरे घर में छींट दिया और 30 अप्रैल की रात अपने प्रेमी संग फरार हो गई।

रात को दो बजे जब परिजनों की नींद खुली तो लड़की के अपने कमरे में न होने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। घरवालों ने किसी अनहोनी की आशंका से पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची



गानले की जानकारी देते एसपी अतुलेश कुमार झा व थाना प्रभारी प्रियंका कुमारी गुप्ता

इंद्रपुरी थानाध्यक्ष प्रियंका कुमारी गुप्ता ने मामले में मिसिंग की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसी कड़ी में

अनुसंधान के दौरान पुलिस ने प्रेमी युगल को मुंबई के ठाणे इलाके के भिवंडी से बरामद किया है। उसके कथित प्रेमी

मयंक कुमार को भी गिरफ्तार कर पुलिस रोहतास लेकर आई है। डिहरी के एसपी अतुलेश झा ने बताया कि आरोपी मयंक अकोढ़ीगोला का रहने वाला है। लड़की के साथ वह फिलहाल मुंबई के ठाणे में रह रहा था। वहीं लड़की ने अपने परिवार को चकमा देने के उद्देश्य से अपने ही घर में मुर्गा का खून फैला दिया, ताकि लोग उसे मरा समझ लें। लेकिन, जब मामलों की गहनता से खानबीन की गई और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जांच की गई तो सच्चाई कुछ और निकली। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार युवक मयंक को ट्रॉजिट रिमांड पर महाराष्ट्र से

मामले में अनुसंधान के दौरान तकनीकी साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की गई। इनपुट के आधार पर लड़की तथा प्रेमी को महाराष्ट्र से बरामद कर लिया गया है। प्रेमी बालिग है। उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, आगे की कार्रवाई जारी है। - अतुलेश झा, एसपी, डिहरी

बिहार लाया गया है। पृष्ठताछ में पता कि दोनों के बीच पिछले 5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की अपने प्रेमी के साथ परिवार और पुलिस को गुमराह कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में जोर-शोर से हो रही है।

दोस्तों ने पहले किया अपहरण, फिर कर दी हत्या, 9 दिन बाद बरामद हुई लाश

नवादा शहर के मिर्जापुर मोहल्ले की घटना, घर से बुलाकर नदी में दफना दिया था शव

AGENCY NAWADA :

जिले के नगर थाने के मिर्जापुर मोहल्ले का 16 वर्षीय प्रिंस कुमार को उसके तीन दोस्तों ने ही घर से बुलाकर ले जाकर हत्या कर लाश को नदी में गाड़ दी थी। भारी मशक्कत के बाद शुक्रवार को पुलिस ने नदी से लाश बरामद कर ली है। आक्रोशित परिजनों ने नवादा सदर अस्पताल के सामने घंटों सड़क जाम रखा। परिजन हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग कर रहे थे। नवादा के सदर एसडीपीओ हुलास कुमार ने बताया कि 13 मई 26 की शाम को नवादा नगर के मिर्जापुर मोहल्ले के संजीत यादव का 16 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार को उनके



शव पहुंचने पर जुटे परिजन व अन्य

तीन दोस्तों ने ही बुलाकर घर से ले गए। लेकिन जब प्रिंस नहीं मिला तो उसके पिता ने 14 मई को नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कुछ लोगों पर शंका भी व्यक्त की। जिसमें से दो

लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर कादिरगंज के निकट सकरी नदी में घोरतानवां गांव के सकरी नदी से लाश बरामद की गई है। एसडीपीओ ने यह भी बताया कि

गिरफ्तार हत्यारों ने कबूल किया है कि टोटो चलाने के कारण झगड़ा हुआ था। जिस कारण तीन लोगों ने मिलकर प्रिंस कुमार को 13 मई को ले जाकर शराब पिलाया। उसके बाद उसकी हत्या कर सकरी नदी में कादिरगंज गांव के घोरतानवां के पास लाश गाड़ दी। एसडीपीओ ने यह भी बताया कि एक अन्य फरार हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी का जा रही है। जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम किया। पुलिस पर शिथिलता बरतने का आरोप लगाते हुए दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने की मांग की गई है।

खराब हुई यात्रियों से भरी नाव एसडीआरएफ ने लोगों को बचाया



रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते एसडीआरएफ के जवान

BHAGALPUR : भागलपुर में गंगा नदी के बीच शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यात्रियों से भरी एक नाव बीच धारा में खराब हो गई। नाव बरारी गंगा घाट से महादेवपुर गंगा घाट जा रही थी। इसी दौरान अचानक नाव का इंजन बंद हो गया और नाव बीच गंगा में ही रुक गई। नाव पर करीब 100 से ज्यादा लोग सवार थे। इनमें महिलाएं, बच्चे और मरीज भी शामिल थे। नाव के बीच नदी में फंसते ही यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई। लोग घबराकर मदद की गुहार लगाने लगे। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ जवानों ने काफी मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं नाव पर सवार लोगों ने बताया कि अचानक इंजन बंद होने से सभी लोग काफी डर गए थे।

वज्रपात की चपेट में आकर मजदूर की मौत

ARARIA :

जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के पलासी गांव में शुक्रवार के दोपहर वज्रपात के चपेट में आने से 59 साल के मजदूर की मौत हो गई। घटना नरपतगंज थाना क्षेत्र के पलासी वार्ड संख्या-2 की है। मृतक की पहचान 58 वर्षीय शंकर पासवान के रूप में की गई है। शंकर पासवान अपने घर में खाना बनाने के लिए जलावन लाने गए थे। इसी दौरान वह वज्रपात के चपेट में आ गया जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों और परिजनों की भीड़ जमा हो गई। इस दुखद घटना से परिवार में मातम छा गया है और सभी गहरे सदमे में हैं। बताया गया है कि मृतक शंकर पासवान की बेटी की शादी तीन दिन पहले ही हुई थी। जो अभी अपने ससुराल में ही है।

आज से सुधा का दूध हो जाएगा 2 रुपये लीटर महंगा, फेडरेशन ने जारी कर दी सूचना

AGENCY PATNA :

बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन (कंफेड) ने सुधा दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें लागू होने के बाद अब ग्राहकों को हर लीटर दूध पर 2 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। इससे पहले अमूल ने भी दो रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दरें 22 मई सुबह से लागू हो गई हैं। पहले सुधा गोल्ड दूध 65 रुपये प्रति लीटर मिलता था, जिसकी कीमत अब बढ़कर 67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। सुधा शक्ति दूध जो पहले 57 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था, अब ग्राहकों को 59 रुपये प्रति लीटर खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा कौंड मिल्क की कीमत में भी 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पहले यह दूध 54 रुपये प्रति लीटर मिलता था, जो अब 56 रुपये प्रति लीटर हो गया है।



राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में सुधा के अलावा आशीर्वाद समेत अन्य डेयरी कंपनियों के उत्पाद भी बिकते हैं। माना जा रहा है कि सुधा दूध के दाम बढ़ने के बाद दूसरी कंपनियां भी जल्द अपने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। दूध की कीमत बढ़ने के बीच राहत की बात यह है कि फिलहाल पनीर, खोवा, छेना और उनसे बने वाली मिठाइयों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी उपभोक्ताओं को इन उत्पादों के

लिए अभी अतिरिक्त पैसे नहीं चुकाने होंगे। कंफेड के अधिकारियों ने बताया कि उत्पादन और परिचालन लागत में बढ़ोतरी के कारण कीमतों में बदलाव करना जरूरी हो गया था। उन्होंने पशु आहार की कीमतों और परिवहन खर्च में हुई भारी बढ़ोतरी का हवाला दिया, जिससे इनपुट लागत काफी बढ़ गई है। अधिकारियों ने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों से डेयरी क्षेत्र लगातार बढ़ती लागत का सामना कर रहा है, जिसके चलते खुदरा कीमतों में सप्ताह-सप्ताह पर बदलाव करने पड़ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले दो सालों में सुधा द्वारा कीमतों में किया गया यह तीसरा बदलाव है। इससे पहले, 21 मई 2025 को, इस सहकारी संस्था ने बिहार में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी।

3 लाख रिश्वत लेते सासाराम के सीओ को निगरानी टीम ने किया गिरफ्तार



पुलिस की गिरफ्त में अंचल अधिकारी

DEHRI : रोहतास जिले के सासाराम निगरानी विभाग की टीम ने सासाराम के अंचलाधिकारी आकाश कुमार रैननिहार को मोरसराय स्थित उनके किराए के आवास से तीन लाख रिश्वत लेते आज गिरफ्तार किया है। निगरानी टीम के अधिकारियों ने बताया कि अंचलाधिकारी के खिलाफ निगरानी थाना पटना में सासाराम आंचल में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार ने सीओ के खिलाफ रिश्वत मांगे जाने की परिवाद दर्ज कराया था। जिसका निगरानी विभाग की टीम ने एक दिन पहले सत्यापन किया था। सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगे जाने की बात सही पाई गई थी। इसके आधार पर आज जाल बिछाए बैठी टीम ने रिश्वत लिए जाने के दौरान उसे रंगे हाथ दबोच लिया। रिश्वत की राशि सीओ अपने एक निजी सहायक सोनू कुमार के माध्यम से ले रहे थे। तभी निगरानी की टीम ने उन्हें रंगे हाथ दबोच लिया। बताते चले कि इसके एक साल पहले सासाराम सीओ का डाटा एंट्री ऑपरेंटर अंचल कार्यालय से एक लाख रुपए रिश्वत लेते निगरानी विभाग की टीम के द्वारा दबोचा गया था।

राजनीति सनातन विरोध की बजाय आममुद्दों पर केंद्रित हो



ललित गर्ग

यह भी सत्य है कि अनेक विपक्षी दल स्वयं को सनातन विरोधी नहीं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों, जातिवाद और भेदभाव के विरोधी बताते हैं। उनका तर्क है कि वे सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं। यह दृष्टि लोकतंत्र में स्वीकार्य है, क्योंकि हर परंपरा में आत्मसमीक्षा और सुधार की आवश्यकता होती है।

भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में एक ऐसा विमर्श लगातार उभर रहा है, जिसने राजनीतिक बहस को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मूल प्रश्नों से हटाकर धार्मिक पहचान और आस्था के इर्द-गिर्द खड़ा कर दिया है। यह विमर्श है-सनातन समर्थन बनाम सनातन विरोध। आज देश में एक ओर सनातन संस्कृति को भारतीय जीवन का शाश्वत आधार मानने वाली शक्तियां हैं, तो दूसरी ओर कुछ राजनीतिक वक्तव्य और प्रवृत्तियां ऐसी दिखती हैं जिन्हें जनमानस सनातन विरोध के रूप में देखता है। प्रश्न यह नहीं कि किसी विचारधारा से सहमति या असहमति क्यों है, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या राजनीति का केंद्र धर्म होना चाहिए या जनजीवन के वास्तविक मुद्दे? भारत का लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष संविधान पर आधारित है, जहां राज्य का कार्य किसी धर्म का पक्ष या विरोध नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। राजनीतिक दलों का दायित्व भी यही होना चाहिए कि वे जनता की समस्याओं, विकास और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दें। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक विमर्श राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है। सनातन केवल एक धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक चेतना, जीवन-दर्शन और मूल्य परंपरा का प्रतीक है। ह्रस्व वद, धर्म चरह, ह्रस्वधैव कुटुम्बकम्ह, ह्रस्वर्षे भवन्तु सुखिनःह जैसे सूत्र इसी सनातन दृष्टि के अंग हैं। इसलिए जब कोई राजनीतिक वक्तव्य सनातन को लेकर अपमानजनक या आक्रामक भाषा का उपयोग करता है, तो उसका प्रभाव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक स्तर पर भी पड़ता है। तमिलनाडु में द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म की तुलना बीमारी से करने वाला वक्तव्य इसी कारण व्यापक विवाद का कारण बना। विपक्ष के अनेक दलों ने उससे दूरी बनाने का प्रयास किया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि भारत जैसे देश में करोड़ों लोगों की आस्था को आहत करने वाला कथन राजनीतिक रूप से भी असहज स्थिति उत्पन्न करेगा। यहां यह समझना आवश्यक है कि द्रविड़ आंदोलन की अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि रही है। उसका मूल संघर्ष सामाजिक विषमताओं और जातीय वर्चस्व के विरुद्ध था। लेकिन जब सामाजिक सुधार का विमर्श पूरे धर्म या संस्कृति के विरोध जैसा प्रतीत होने लगे, तब वह जनस्वीकृति खो देता है। यह भी सत्य है कि अनेक विपक्षी दल स्वयं को सनातन विरोधी नहीं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों, जातिवाद और भेदभाव के विरोधी बताते हैं। उनका तर्क है कि वे सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं। यह दृष्टि लोकतंत्र में स्वीकार्य है, क्योंकि हर परंपरा में आत्मसमीक्षा और सुधार की आवश्यकता होती है। स्वयं भारतीय दर्शन में



भी संवाद, बहस और आत्मचिंतन की परंपरा रही है। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, दयादंर और गांधी-सभी ने समाज की विसंगतियों पर प्रश्न उठाए, लेकिन उन्होंने समाज को तोड़ने नहीं, सुधारने का मार्ग चुना। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक भाषा संतुलन खो देती है। जब आलोचना सुधार की जगह अस्वीकार की भाषा बन जाती है, तब वह समाज में ध्रुवीकरण को जन्म देती है। भारत जैसे बहुलतावादी देश में यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं कही जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का विमर्श अधिक प्रभावी होकर उभरा है। राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरुत्थान जैसे विषयों ने एक बड़े वर्ग में सांस्कृतिक आत्मविश्वास को मजबूत किया है। इससे भारतीय जनता पाटी को राजनीतिक लाभ भी मिला। दूसरी ओर विपक्षी दल इस बदलते राजनीतिक मानस को समझने में कई बार असहज दिखाई दिए। कहीं उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और आस्था के बीच संतुलन बनाने में चूक की, तो कहीं उनके कुछ नेताओं के बयान उन्हें कठिन स्थिति में ले आए। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक चुनावी राजनीति में यह देखा गया कि केवल जातीय समीकरण या पारंपरिक वोट बैंक अब पर्याप्त नहीं हैं। जनता सांस्कृतिक पहचान, विकास और राष्ट्रीय विमर्श को भी महत्व देने लगी है। ऐसे में यदि कोई दल हिंदू आस्था के प्रति असंवेदनशील दिखता है, तो उसका राजनीतिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरे विमर्श का दूसरा पक्ष भी है। क्या राजनीति का उद्देश्य केवल धार्मिक पहचान के आधार पर समर्थन जुटाना होना

चाहिए? क्या देश के सामने मौजूद बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि संकट, आर्थिक असमानता और सामाजिक विघटन जैसे प्रश्न पीछे छूट जाने चाहिए? यह चिंता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों के दौरान धर्म, विशेषकर सनातन और हिंदू आस्था को लेकर कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक आदि विपक्षी दलों एवं उनके कुछ नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को व्यापक जनसमुदाय ने सनातन पर आक्षेप या हिंदू भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता के रूप में देखा, जिसके राजनीतिक प्रभाव भी दिखाई दिए। किंतु इस विषय को केवल ह्रिंहिंदू विरोध कहना गड़बड़ करती है। यही कारण है कि कई दलों के लिए यह धारणा चुनौती बनी कि वे सत्ता-विरोध की राजनीति करते-करते सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनाओं से दूर हो गए हैं। भारत में सनातन केवल धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन, परंपरा, संस्कृति, सहिष्णुता और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसके प्रति असावधान भाषा या नकारात्मक संकेत जनमानस में प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करते रहे हैं। दूसरी ओर लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा यह भी अपेक्षा करती है कि राजनीतिक विमर्श व्यक्तियों, नीतियों और शासन के मुद्दों पर केंद्रित रहे, न कि धार्मिक ध्रुवीकरण पर। राजनीतिक दलों के लिए यह आवश्यक है कि वे मतभेद

रखें, आलोचना करें, लेकिन भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक संवेदनशीलता और आस्था के सम्मान का संतुलन बनाए रखें, क्योंकि जनता अंततः उसी नेतृत्व को स्वीकार करती है जो उसकी भावनाओं, परंपराओं और राष्ट्रीय मानस को समझने का प्रयास करता है।

भारत की राजनीति को ह्र्दयमं बनाम धर्मह की लड़ाई से ऊपर उठकर ह्र्जन बनाम जनसमस्याह के विमर्श की ओर बढ़ना होगा। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि जनता मंदिर भी चाहती है और रोजगार भी, आस्था भी चाहती है और अवसर भी, संस्कृति भी चाहती है और आधुनिकता भी। केवल धार्मिक ध्रुवीकरण किसी राष्ट्र की स्थायी प्रगति का आधार नहीं बन सकता। आज आवश्यकता है कि राजनीतिक दल सनातन विरोध या हिंदू विरोध जैसे आरोप-प्रत्यारोपों की राजनीति से बाहर निकलें। यदि किसी परंपरा में सुधार की बात करनी है, तो वह सम्मानजनक भाषा और रचनात्मक दृष्टि से हो। सामाजिक न्याय का अर्थ सांस्कृतिक अस्वीकार नहीं होना चाहिए और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अर्थ अन्य दृष्टियों का निषेध भी नहीं होना चाहिए। भारतीय सभ्यता की शक्ति उसकी विविधता और सहिष्णुता रही है। यहां शंकराचार्य भी हैं, बुद्ध भी हैं, महावीर भी हैं, कबीर भी हैं, वेद भी हैं और संविधान भी। भारत ने सदैव संवाद को संघर्ष से ऊपर रखा है। इसलिए राजनीति का भी दायित्व है कि वह समाज को जोड़ने वाली भाषा बोले। आज जब विश्व संघर्षों, सांस्कृतिक तनावों और पहचान की राजनीति से जूझ रहा है, तब भारत के पास ह्र्बहुवचन कुटुम्बकम्ह का संदेश है। यही सनातन का वास्तविक स्वरूप भी है-समावेश, करुणा और सहअस्तित्व। राजनीतिक दलों को आत्ममंथन करना होगा कि वे जनता को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं-धार्मिक टकराव की ओर या राष्ट्रीय निर्माण की ओर? यदि राजनीति केवल आस्था के विवादों में उलझी रही, तो जनजीवन के वास्तविक प्रश्न पीछे छूट जाएंगे। लेकिन यदि राजनीति संस्कृति का सम्मान करते हुए विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याओं के केंद्र बनाएगी, तो भारत एक संतुलित और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। सनातन का अर्थ शाश्वत है, और शाश्वत वही होता है जो सबको साथ लेकर चले। इसलिए किसी भी प्रकार का अंध-विरोध या अंध-समर्थन समाधान नहीं हो सकता। आवश्यकता है विवेकपूर्ण दृष्टि, संतुलित राजनीति और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की। भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता इसी में है कि वह आस्था का सम्मान करे, लेकिन राजनीति को जनहित का माध्यम बनाए। तभी लोकतंत्र की मजबूत होगा और समाज भी समरस बनेगा।

1975 का आक्रोश और 2026 का बैचैन भारत?

संपादकीय

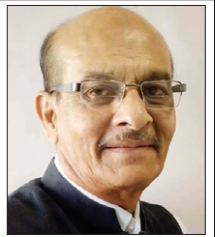
लू से हलकान जिंदगी

हाल के दिनों में आसमान से बरसती आग से देश में जन-जीवन बुरी तरह झुलस रहा है। रोज तापमान बढ़ने के नये रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। ये असहनीय तापमान केवल स्वास्थ्य की चुनौती मात्र नहीं है, बल्कि एक आर्थिक संकट भी है। देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक भीषण गर्मी में काम करने को मजबूर हैं। यदि वे ऐसा न करें तो उनके सामने आजीविका का संकट पैदा हो जाता है। स्कूल-कालेज तो लू के दौरान बंद किए जा सकते हैं, सरकारी व गैर सरकारी दफ्तरों में काम के घंटों में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन खेत में काम करने वाले खेतिहर मजदूर व निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को तो तपती दोपहरी व लू के बीच काम करने को मजबूर होना पड़ता है। दरअसल, लू की मार जहां शारीरिक है, वहीं आर्थिक भी। लगातार बढ़ते तापमान से लोगों की आजीविका और श्रम उत्पादकता पर बुरा असर पड़ रहा है। इस संकट को हल के दिनों में हुई ईंधन की कीमतों की वृद्धि और महंगाई ने और बढ़ा दिया है। लोगों को सीमित संसाधनों में जीवन यापन को मजबूर होना पड़ रहा है। विडंबना यह है कि इस संकट का सबसे घातक प्रभाव उस तबके को सहन करना पड़ता है जो हटारोज कुंआ खोदकर पानी पीनेह्द को बाध्य है। एक दिन की कमाई से ही रात को उसके घर का चूल्हा जलता है। लू के निशाने पर वे अनौपचारिक श्रमिक हैं जो भारतीय आर्थिकी की रीढ़ हैं। सही मायनों में लू के खिलाफ लड़ाई को अब केवल एक मौसमी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या ही नहीं माना जा सकता है। धीरे-धीरे यह एक गंभीर आर्थिक चुनौती भी बनी है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बाबत चेतावते रहे हैं। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनुमान लगाया था कि लू से उपजे हालात से भारत को सी अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। इससे पहले वर्ष 2022 में विश्व बैंक ने चेतावनी दी थी कि भारत का तीन-चौथाई श्रमिक वर्ग लू से प्रभावित क्षेत्रों में काम करने को मजबूर है। अनुमान है कि लू के तनाव के कारण होने वाली विश्वव्यापी नौकरियों की कमी में भारत की हिस्सेदारी आधी हो सकती है। दरअसल, भारत में सबसे अधिक जोखिम वाले समूहों में निर्माण श्रमिक, खेतिहर श्रमिक, किसान, स्ट्रीट वेंडर और डिलीवरी एजेंट शामिल हैं। हालांकि, समय-समय पर केंद्र व राज्य सरकारों ने कार्य समय का पुनर्निधारण, छायादार विश्राम क्षेत्र बनाने, जलपान सुविधा, सुरक्षात्मक कपड़े और स्वास्थ्य निगरानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है,लेकिन फिर भी संकट के दायरे को देखते हुए ये उपाय नाकामी हैं। देखा जाए तो फिजहाल भारत में गर्मी के संकट से मुकाबले के लिये बनायी गई योजनाएं काफी हद तक अस्थायी रूप से राहत देने वाली हैं। वक्त की मांग है कि भीषण गर्मी वाले महीनों के लिये तत्काल व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार किया जाए।

चिंतन-मनन

संकल्प और साहस

खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली-पतली अपंग लड़की किसी तरह अपनी जगह से उठी। वह खेलों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करते हुए शिक्षक से ओलिंपिक रेकोर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर सभी छात्र हंस पड़े। शिक्षक ने भी व्यंग्य किया- तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी। अपने ऊपर कभी नजर डाली है? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, फिर ओलिंपिक से तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें कौन सा खेलना है जो यह सब जानोगी। चुपचाप बैठकर सुनो। रुआंसी लड़की कुछ कह न सकी। सारी क्लास उस पर हंसती रही। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियां संभालीं और दृढ़ निश्चय के साथ बोली-सर याद रखिएगा। अगर लगन सच्ची हो और इरादे बुलंद हों तो सब कुछ संभव है। आप देखना एक दिन यही लड़की हवा से बातें करके दिखाएंगी। उसकी इस बात से भी ठहाका गूंज उठा। सबने इसे मुजाक के रूप में लिया। लेकिन वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी, फिर वह कुछ दिनों में दौड़ने भी लगी। कुछ दिनों के बाद उसने छोटी-मोटी दौड़ में भाग लेना भी शुरू कर दिया। उसे दौड़ते देख लोग दाँते उंगली दबा लेते थे। फिर कई लोग उसकी मदद को आगे आए। सबने उसका उत्साह बढ़ाया। उसके हाँसले बुलंद होने लगे। फिर उसने 1960 के ओलिंपिक में हिस्सा लिया और तीन स्वर्ण पदक जीतकर सबको हतप्रभ कर दिया। ओलिंपिक में इतिहास रचने वाली वह थी अमेरिकी धाविका विल्मा रुडोल्फ।



सनत जैन

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 1975 केवल एक वर्ष नहीं, बल्कि सत्ता, आर्थिक संकट और जनक्रोश के टकराव का प्रतीक भी है। 2026 में देश की परिस्थितियों को देखकर बार-बार 1975 की महंगाई का वही प्रश्न उठता है, क्या भारत फिर किसी बड़े राजनीतिक और सामाजिक विस्फोट की ओर बढ़ रहा है? जिसमें सत्ता का परिवर्तन भी हुआ था। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर बांग्लादेश का निर्माण करया था। करीब एक करोड़ शरणार्थियों का बोझ भारत ने उठाया। पाकिस्तानी सेना के 95000 से अधिक जवान आत्मसमर्पण कर भारत में रहे। युद्ध के



किशन सममुखदास

चुनौती याचिका 20 मई 2026 को खारिज-संवैधानिक वैधता, सामाजिक न्याय और भारत की नई नीति- व्यवस्था की दिशा का व्यापक समग्र विश्लेषण... भारत की जनगणना 2027 डिजिटल इंडिया और डेटा-आधारित गवर्नेंस के सबसे बड़े प्रशासनिक अभियानों में से एक माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का 20 मई 2026 का यह फैसला केवल एक याचिका खारिज करने तक सीमित नहीं है।बल्कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय की अवधारणा और डेटा- आधारित शासन प्रणाली के भविष्य को दिशा देने वाला निर्णय. वैश्विक स्तरपर भारत में वर्षों से चल रही जातिगत जनगणना की बहस को बुधवार 20 मई 2026 को एक निर्णायक मोड़ तब मिला, जब भारतीय सुप्रीमकोर्ट ने जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले ने केवल एक कानूनी विवाद का अंत नहीं किया,बल्कि यह स्पष्ट संदेश भी दे दिया कि भारत में होने वाली जनगणना 2027 पूरी तरह संवैधानिक,कानूनी और नीतिगत अधिकारों केद्वारे में संचालित की जा रही है। बता दें इसके पूर्व भी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (11 अप्रैल, 2026) को केंद्र को जाति जनगणना रोकने का निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दियाथा और जनहित याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा के लिए याचिकाकर्ता की कड़ी आलोचना की। पिछले कुछ महीनों से जातिगत जनगणना को लेकर राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक स्तर पर तीखी बहस चल रही थी। कुछ वर्ग इसे सामाजिक न्याय का आधार बता रहे थे, जबकि विरोधी पक्ष इसे सामाजिक विभाजन बढ़ाने वाला कदम कह रहा था। किंतु सर्वोच्च

अदालत के ताजा निर्णय ने यह स्थापित कर दिया कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को यह अधिकार है कि वह देश की सामाजिक संरचना, विशेषकर पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या और स्थिति को समझने के लिए डेटा एकत्र करे, ताकि उसके आधार पर कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकें। मैं एडवोकेट किशन सममुखदास भावनांनी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूँ कि भारत की जनगणना 2027 केवल एक पारंपरिक जनगणना नहीं मानी जा रही,बल्कि इसे डिजिटल इंडिया और डेटा-आधारित गवर्नेंस के सबसे बड़े प्रशासनिक अभियानों में से एक माना जा रहा है। लगभग डेढ़ सौ वर्षों से चली आ रही जनगणना व्यवस्था अब तकनीकी रूप से आधुनिक स्वरूप में प्रवेश कर चुकी है। साथियों इस बार की जनगणना दो बड़े चरणों में आयोजित की जा रही है।पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हुआ,जिसमें हाउस लिस्टिंग और आवासीय गणना की प्रक्रिया अपनाई गई। 16 अप्रैल से 15 मई 2026 तक चले इस चरण में देशभर के घरों,संपत्तियों,भवनों, आवासीय सुविधाओं, जल स्रोतों, बिजली, इंटरनेट, शौचालय, रसोई, वाहन और सामाजिक- आर्थिक आधारभूत संरचनाओं से संबंधित डेटा संकलित किया गया।वह चरण केवल जनसंख्या गिनने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह देश की जीवन- स्थितियों का व्यापक सामाजिक -आर्थिक सर्वेक्षण भी बन गया।जनगणना का दूसरा चरण वर्ष 2027 में प्रारंभ होगा, जिसमें प्रत्येक परिवार और उसके सदस्यों की विस्तृत व्यक्तिगत जानकारी दर्ज की जाएगी। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है जिसमें मोबाइल ऐप, ब्रेलेट आधारित डेटा एंटी, ऑनलाइन सत्यापन और केंद्रीकृत डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि डेटा आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। यही कारण है कि जातिगत आंकड़ों का समाजिक न्याय की जाणीए। इसमें आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा, वैवाहिक स्थिति, प्रवासन, सामाजिक श्रेणी और विशेष रूप से जातिगत विवरण शामिल होंगे। पहली बार इतनी व्यापक डिजिटल प्रणाली

Can't keep failing our students

The cancellation of NEET-Undergraduate 2026 has pushed nearly 23 lakh students across India into uncertainty, anxiety and emotional distress. These candidates undertook months and years of disciplined preparation, believing that the Union government would at least ensure a fair and secure examination process. Instead, in one stroke, the system has pushed them into confusion and instability. What should have been a transparent and merit-based gateway to medical education has instead become a symbol of institutional failure, administrative negligence and the dangerous collapse of public trust in our exam systems.NEET is not simply a competitive exam. It represents aspiration, social mobility, economic hope and years of personal sacrifice. Parents invest heavily, exhausting savings, taking loans and stretching their finances to the limit to support their children’s dreams of entering the medical profession. The collapse of exam integrity, therefore, becomes not merely an academic disruption, but a major social and economic crisis.

The most serious consequence of repeated exam controversies is the erosion of public confidence in our institutional systems. High-stake national exams derive their legitimacy from trust. The moment students begin to believe that merit can be compromised through organised malpractice, impersonation, paper leaks or corrupt networks, the credibility of the entire system weakens.

The NEET-UG 2024 controversy had already shaken public confidence after allegations of paper leaks, suspicious score inflation, grace marks and procedural irregularities triggered nationwide protests. Eventually, a re-exam had to be conducted for 1,563 candidates who were awarded grace marks due to alleged loss of exam time. Yet, the lessons were evidently ignored. Instead of structural reform, the country witnessed routine assurances and temporary damage control.The recent cancellation demonstrates that the crisis is not accidental, but systemic. Since the introduction of NEET, allegations of irregularities, impersonation, organised cheating and paper leaks have repeatedly surfaced across multiple states. Nor is the problem confined to NEET alone. In 2024, UGC’s National Eligibility Test was cancelled within a day over suspected leaks, while the joint Council of Scientific and Industrial Research-UGC NET and NEET-Postgraduate were postponed amid allegations of security breaches and procedural failures. These incidents collectively indicate the existence of a deep-rooted nexus involving coaching mafias, organised cheating syndicates, corrupt intermediaries an institutional negligence.

The psychological consequences are enormous. Students preparing for exams like NEET endure extraordinary academic pressure for one or two years, often sacrificing social life, recreation, emotional well-being and extracurricular growth. When the integrity of the exam collapses, the resulting uncertainty creates anxiety, helplessness, frustration, humiliation and loss of confidence.The National Testing Agency (NTA), entrusted with conducting some of the country’s most critical exams, has repeatedly failed

Made in Italy + Make in India = Excellence

The Indo-Pacific and the Mediterranean are increasingly interconnected spaces

THE relationship between India and Italy has now reached a decisive stage. In recent years, our ties have expanded with unprecedented momentum, evolving from a cordial friendship into a special strategic partnership grounded in the values of freedom and democracy, and a common vision for the future.At a time when the international system is undergoing a profound change, the partnership between Italy and India is guided by regular exchanges at high political and institutional levels and is gaining a new and higher dimension that combines our economic dynamism, societal creativity and millennia-old civilisational wisdom.

Our cooperation mirrors our shared awareness that prosperity and security in the 21st century will be shaped by the ability of nations to innovate, manage energy transitions and strengthen strategic sovereignty.

To this end, we have committed to deepening and diversifying our bilateral relationship with a view to pursuing new objectives and pooling our complementary strengths.We aim to forge a powerful synergy between Italian design, manufacturing excellence and world-class supercomputers — reflecting Italy's position as an industrial powerhouse — and India's rapid economic growth, engineering talent, scale and innovation and entrepreneurial ecosystems with over 100 unicorns and 200,000 startups. This is not a simple integration, but a co-creation of value where our respective industrial strengths amplify one another.The Free Trade Agreement between the European Union and India paves the way for increased trade and investment in both directions. We want to reach and exceed the Euro 20 billion target for trade between Italy and India by 2029, with a focus on defence and aerospace, clean technologies, machinery, automotive components, chemicals, pharmaceuticals, textiles, agri-food, tourism and more.'Made in Italy' has been synonymous with excellence, and today, it finds a natural synergy with the high-quality goals of the 'Make in India' initiative. The growing interest of Italian businesses in production in India and the increasing presence of Indian industries in Italy, numbering over 1,000 from both sides now, is a positive sign that will strengthen the integration of our supply chains.Technological innovation lies at the very heart of our partnership. The coming decades will be shaped by a technological revolution of unmeasurable scope, marked by advances in sectors such as artificial intelligence, quantum computing, advanced manufacturing, critical minerals and digital infrastructure. India's dynamic innovation ecosystem, coupled with the highly skilled professional talent pool and Italy's advanced industrial capabilities make our cooperation in the above sectors both natural and

strategic. The growing partnership between our universities and research centres will support this. India's digital public infrastructure is already finding resonance with a large number of countries, particularly in the Global South.Artificial Intelligence, in particular, is impacting our societies and the global economy. Italy and India have long been collaborating to ensure that AI development is responsible and human-centred. From this perspective, India and Italy also see AI as a powerful instrument for inclusive development, especially for the Global South, where digital public infrastructure and



accessible, multilingual technologies can bridge divides rather than deepen them. Building on India's vision of MANAV — putting humans at the centre of technology — and Italy's leadership in promoting a human-centric 'algor-ethics' rooted in its humanist tradition, our partnership seeks to ensure that AI acts as a catalyst for social empowerment. Our approach combines India's digital scale with Italy's ethical and industrial expertise, ensuring tech serves human dignity.By sharing best practices in secure digital cooperation, capacity-building and resilient cyber infrastructure, we aim to create an open, trustworthy and equitable digital space in which every nation can shape and benefit from AI. This perspective forms the core of Italy's G7 Presidency and outcomes of the AI Impact Summit 2026, held in New Delhi. Conceiving AI as a tool created by humans for humans means firmly asserting that technology cannot replace individuals or undermine their fundamental rights, nor be used to manipulate public debate or alter democratic processes.

Our cooperation also covers the space sector. India's advancements in space exploration and satellite technology, together with Italy's aerospace engineering excellence, offer significant opportunities for joint initiatives and next-generation technology

development.Security and stability remain essential to ensuring nations' prosperity. Italy and India intend to further strengthen their cooperation in defence, security and strategic technologies. Our collaboration will help ensure the security of critical maritime routes, strengthen resilience in the face of threats, such as terrorism, international criminal networks, drug trafficking, cybercrime and human trafficking.Energy is another key pillar of our partnership. The global transition towards diversified energy sources requires innovation, investment and cooperation. India and Italy are collaborating on areas ranging from renewable energy and hydrogen technologies to smart grids and resilient infrastructure to become a hub for green hydrogen exports offers immense potential, it complements Italy's advanced technology in renewable infrastructure and its strategic role as an energy gateway for Europe. Our collaboration with other countries through key India-led initiatives — the International Solar Alliance, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure and Global Biofuels Alliance — is also important in this context.Physical, digital and human connectivity is the thread that weaves us together. Both India and Italy are located at the very heart of two crucial hubs of the global economy — the Indo-Pacific and the Mediterranean. These regions cannot be viewed as separate spheres, but instead, as increasingly interconnected spaces.

We are witnessing the emergence of what might be termed the Indo-Mediterranean, an important corridor for trade, technology, energy, data and ideas tying the Indian Ocean to Europe. It is precisely within this interconnected space that our bond naturally evolves into a special strategic partnership — one that bridges two continents and shapes new global dynamics.The India-Middle East-Europe Economic Corridor represents a vision aimed at better connecting our regions through transport and infrastructure, digital networks, energy systems and supply chains. India and Italy are also committed to working together with other partners to make this vision a reality.We can address our shared challenges by drawing upon our partnership and the enduring cultural ties between us. Within the Indian culture, the concept of 'dharma' evokes the sense of responsibility that must guide our actions, whilst the principle of 'vasudhaiva kutumbakam' (the world is one family) resonates powerfully in this interconnected digital age.Such values find a natural echo in Italy's humanist tradition, rooted in the Renaissance, which highlights the dignity of each individual and the power of culture to unite peoples and societies. Our shared vision, therefore, aims to lay the foundation for a strong and forward-looking India-Italy partnership, with our people at the centre.

Dog menace : SC balances public safety with animal welfare

India recorded over 30 lakh dog-bite cases in 2023, followed by more than 37 lakh cases in 2024

THE Supreme Court’s refusal to dilute its directions on removing stray dogs from public institutions is a necessary intervention in a worsening public safety crisis. For years, civic authorities across India have failed to address the alarming rise in dog-bite incidents, forcing courts to step into what is essentially an administrative vacuum. As per the National Centre for Disease Control, India recorded over 30 lakh dog-bite cases in 2023, followed by more than 37 lakh cases in 2024 — averaging over 10,000 incidents every day. Several states and cities are witnessing an unprecedented surge. Kerala recently reported more than 3.6 lakh dog-bite cases within a year, while Noida identified dozens of dog-bite hotspots after tens of thousands of complaints in just a few months. Behind these statistics are children attacked near schools, elderly citizens unable to walk safely and residents living in fear of aggressive stray packs.At the



same time, the crisis reflects a deeper failure in how society and institutions treat animals. A couple of days

ago, a shocking incident emerged from Chandigarh, where a puppy was reportedly thrown into a tandoor by an unidentified person. Such acts expose the disturbing cruelty that often exists beneath public debate. Equally troubling is the condition of many dog pounds and shelters. Reports from Chandigarh have highlighted deplorable conditions, including instances of dogs allegedly eating their own young due to neglect.

The SC has rightly held that humane treatment of animals cannot mean ignoring human safety, but neither can public safety become a justification for neglecting animal welfare. The SC’s emphasis on lawful relocation must now be matched by investments in shelters, sterilisation centres, vaccination drives and veterinary facilities. The challenge is to build a humane, accountable and effective stray management system that protects both citizens and canines.

Xi has the measure of Trump

Clearly, the Chinese see the scales tilting increasingly in their favour

IF the summit between US President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping in Beijing last week was expected to bring the world closer to peace in West Asia, that was a bar set too high already. The two sides certainly “exchanged views on major international and regional issues, such as the Middle East situation, the Ukraine crisis and the Korean Peninsula”, but the record shows that they have diametrically opposite views on what the outcome of each conflict ought to be.

On the Korean Peninsula, the Chinese are strenuously opposed to the presence of American troops in South Korea, but despite their misgivings about North Korea’s nuclear programme, are not about to press Pyongyang too hard on the issue if it keeps the Americans on tenterhooks. Plus, the regime is a bulwark against American troops on China’s borders.

On the Ukraine crisis, China has committed to a ‘no limits’ partnership with the Russians. While Beijing perhaps expected a quick Russian victory, the stalemate also suits it just fine with Russia on the ropes and dependent on China’s financial system, military supplies and diplomatic support, and trans-Atlantic unity fraying under US pressure on the Europeans to increase their defence budgets.The US-Israel attack on Iran has perhaps affected the Chinese the most over the short term at least with rising energy prices. China has the largest strategic oil reserves of any country on the planet and can be expected to bear the pain longer than most countries – even so, prolonged economic distress in the Global South has consequences for China that has



foreign policy, it is that whatever the diplomatic rhetoric, Beijing has always acted only in its own interest. Its markets in the Global South are not so large or important right now as to cause it to veer from a larger interest — seeing the US dragged into another morass of its own making and distracted from focusing its full attention on

China.At a recent conference in Berlin that this author attended, at least one Chinese participant suggested that the Iran conflict was a good thing for China in the short term because it had diverted US military resources from the Indo-Pacific to the Arabian Gulf. With a limited number of US aircraft carriers in East Asian waters — there is just one currently according to the US Navy — the implication was that China fancied its chances in a Taiwan scenario. While this might have simply been kite-flying, the larger logic of the US being too involved in other theatres to focus on China still holds.

It is no surprise then that the Chinese have done their bit to bolster Iran’s capabilities. There is no mention of any Chinese commitment whatsoever to helping the US end the Iran conflict, even though the readout from the White House stated, “Both countries agreed that Iran can never have a nuclear weapon.” But China does not necessarily disagree with this proposition nor the need to keep the Strait of Hormuz open for the free flow of energy — it is just that it does not feel the need to actively work to these ends if the US finds these objectives more important. Higher prices for domestic consumers have more political consequences for Trump than they do for Xi.

Indeed, this Chinese view extends to the larger economic relationship and outcomes of the Trump visit. Several economic agreements have been concluded, but the Chinese official media reportage is interesting. It quotes Trump as saying to Xi “that the world’s top companies all wanted to come to China” and that he “actively encouraged them to expand their cooperation with China”. The message that the Chinese

will take from this is that the Americans need the Chinese market more than the other way round, even if for Chinese manufacturers, too, it is the American market that matters more than anything in the Global South.As the Chinese see it though, “In the blink of an eye, US-China relations have evolved into what the United States views as a relationship between nearly equal nations.” But in language redolent of hierarchy and imperialism, the Chinese Foreign Ministry also stated that “President Trump asked each of the [American] business leaders who were travelling with him to present themselves to President Xi.” Clearly, the Chinese see the scales tilting increasingly in their favour.

It is this confidence that allowed China to push the US more strongly than it has ever done on the issue of Taiwan. Calling it “the most important issue in China-US relations”, Xi threatened “clashes and even conflicts” if the issue was not “handled properly”. But there is only one way that this can be done, which is for the Americans to unequivocally support the Chinese position on Taiwan.Despite China’s multitud of internal problems, including the hit its manufacturing sector has taken from the US-Iran conflict and rising fuel prices, the language coming out of Beijing suggested a greater degree of confidence that it ever did before.

While Trump was a wild card in his first term that the Chinese took time to figure out how to deal with, they did figure him out as they ignored much of the deals cut with him during that time.

This time round, with Trump clearly under external and domestic pressure from the continuing conflict with Iran, Xi appeared to have the measure of his guest and was willing also to engage in more direct language alongside the diplomatic pomp and ceremony.

Sensex, Nifty open higher as crude stays near \$105; banks, financials lead gains

New Delhi,.(Agency)
Benchmark stock market indices opened higher on Friday as investors tracked crude oil prices and developments in the ongoing US-Iran talks, while banking and financial stocks led gains in early trade. The BSE Sensex was up 336.46 points at 75,519.82 around 9:26 am, while the NSE Nifty50 gained 86.30 points to trade at 23,741.00.Markets opened with positive momentum after global crude oil prices remained below the \$105-per-barrel mark despite continuing tensions in West Asia.As of around 9:25 am, Brent crude was trading at \$104.25 per barrel, up 1.63%, WTI crude stood at \$97.44 per barrel, up 1.13%

OIL, IRAN TALKS REMAIN IN FOCUS
Investors are closely watching developments in the US-Iran peace discussions, which continue to influence global oil prices and market sentiment. The two sides remained divided on issues related to Iran’s uranium stockpile and control over the Strait of Hormuz, although US Secretary of State Marco Rubio said there had been “some good signs” in the negotiations. The Iran conflict has remained one of the biggest triggers for global markets over the past few months, especially for oil-importing countries like India.

BANKING SHARES LEAD MARKET GAINS
Most major sectors traded in the green during early trade.Nifty Financial Services rose 0.76%, while Nifty Private Bank gained 0.93% and PSU Bank index climbed 0.47%.IndiGo shares also rose more than 0.8%, while UltraTech Cement, Asian Paints and Axis Bank traded higher.However, IT stocks remained under pressure, with Tech Mahindra, Infosys and TCS slipping in early trade.

LIC stock in focus: Q4 profit surges 23%, board announces Rs 10 dividend

Kolkata .(Agency)
LIC Q4 results which were announced after market hours on May 21 beat market expectations on most core performance parameters. LIC announced a 23% surge in its Q4FY26 net profit figure, which jumped to Rs 23,467 (on a year-on-year basis) against Rs 19,039 crore in Q4FY25. The company’s board of directors spiced up the robust results with a dividend of Rs 10 per share for shareholders. It is expected that LIC shares will see significant movement today, May 22. LIC’s assets under management (AUM) increased 5.1% year-on-year to touch Rs 57.3 lakh crore. The value of new business (VNB) also saw a significant jump and in the Jan-March quarter, it surged 41.63% to reach Rs 14,179 crore, which signalled improved profitability in generating new business.
Improvement in solvency ratio
LIC’s solvency ratio increased to 2.35% during the Q4 period compared to 2.11% in the same period last year. It stood at 2.19% in the Q3FY26 period. The solvency ratio of an insurer reflects its financial strength. However, the company’s 13-month persistency ratio declined to 67.77% compared to 68.62% last year and 69.36% in Q3FY26 period.
Preparations for IndAS implementation
LIC said that the company is preparing to implement Indian Accounting Standards (IndAS) as per regulatory guidance and is confident of implementing it within the stipulated time frame.
“Financial Year 2025-26 has been a satisfying year for us, with strong overall growth across every business vertical leading to record performance metrics. We have achieved a Non Par share on APE basis in our individual business of more than 35% and our VNB margin is more than 21% for the year. Our strategy of channel diversification has been successful with our Banca and Alternate Channels (BAC) having recorded a growth rate of more than 45% with premium from BAC exceeding Rs. 5,000 Crores in FY26,” said R Doraiswamy, CEO and MD of LIC.

Capital Group builds \$2 billion bet in Adani Group in pivot from Reliance

New Delhi.(Agency)
The Capital Group, one of the world’s largest investment management firms, has been increasing its exposure to Adani Group companies while steadily paring holdings in Reliance Industries Ltd., marking a shift in foreign investor preference between India’s biggest conglomerates. The Los Angeles-based money manager has acquired stakes worth more than \$2 billion across three Adani Group companies in recent weeks, according to people familiar with the matter. On May 5, Capital Group bought nearly a 2 per cent stake in Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. for ?74.86 billion (\$776 million) through open-market transactions, according to BSE block-deal data. The investor, which oversees more than \$3.3 trillion in assets globally, has also accumulated between 1.5 per cent and 2 per cent stakes in Adani Power Ltd. and Adani Green Energy Ltd. through market purchases, the people said, asking not to be identified because the information is private. In a market that’s fallen out of favor with some investors because of its lack of companies tied to the global artificial intelligence buildup, Adani companies are increasingly viewed as rare leveraged plays on India’s infrastructure development, energy transition and manufacturing push. That shift is also emblematic of a broader transition toward bets on the next phase of India’s economic expansion. Adani Power, Adani Green and Adani Ports shares surged 94 per cent, 35 per cent and 25 per cent, respectively, in one year A Capital Group spokeswoman said she’s unable to comment on individual stocks or shareholdings. A representative for Adani Group didn’t respond to a request for comment.

Rupee at 100 against US dollar? Why experts say India shouldn't panic

As crude oil prices stay elevated and the rupee weakens further, a growing number of experts now argue India's real risk is not crossing 100 against the dollar, but rising inflation and slowing growth.

New Delhi,.(Agency)
The rupee has been on a roller-coaster ride in recent months, sliding sharply against the US dollar as the global oil shock deepens and tensions in West Asia continue to disrupt energy markets. With crude oil prices remanding above \$100 per barrel amid the ongoing West Asia conflict, many economists now believe the rupee touching 100 against the dollar may no longer be unthinkable.And interestingly, a growing number of experts also argue that the real risk for India may not be the rupee touching 100 itself, but what happens to inflation, jobs and economic stability alongside it.Former IMF Deputy

Managing Director and Harvard University professor Gita Gopinath recently captured this shift in thinking when she argued that policymakers should focus less on the symbolic exchange-rate level and more on the broader economy.“The relevant number is not the actual value of the exchange rate,” Gopinath said in a recent interview.“What matters is jobs, inflation and output,” she said. That view is increasingly finding support among economists and market experts as India navigates a worsening global energy crisis.
A WEAKER RUPEE IS NOT ALWAYS BAD
For years, rupee weakness was often viewed almost entirely as a sign of economic stress. But economists say currency depreciation during a major external shock is not automatically a bad thing.In fact, a weaker rupee can sometimes help economies adjust. When the rupee falls, imports become more expensive. That naturally reduces

demand for foreign goods, lowers pressure on India’s foreign exchange reserves and can improve export competitiveness by making Indian products cheaper globally. “Rupee depreciation is partly a problem and partly a solution to the problem,” said Dr. VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist at Geojit Investments Limited. “Rupee depreciation boosts exports and at the same reduces foreign exchange



expenditure. Expensive dollar can curtail forex expenditure more than austerity appeals. That way it is a solution to the problem,” he added.This logic becomes especially important during oil shocks. India imports the majority of its crude oil requirements. With tensions around the Strait of Hormuz disrupting global energy flows, elevated oil prices are already increasing pressure on India’s import bill and dollar demand.In such situations, economists argue that allowing the currency to weaken gradually can help absorb part of the shock instead of forcing the Reserve Bank of India (RBI) to aggressively burn through forex reserves defending a symbolic exchange-rate level.
'100 IS JUST A NUMBER'
The growing argument against aggressively defending the rupee has also found support from former NITI Aayog Vice Chairman and Chairman of the 16th Finance Commission Arvind Panagariya.

Why is Indian rupee slipping nonstop? Here are three triggers behind the fall and risks ahead

New Delhi.(Agency)
India’s economy continues to grow at a healthy pace, but the rupee has been under depreciation for years. The currency has now moved close to the 97-per-dollar mark, and it has fallen by nearly 7.5 percent in the first months of 2026. This leads to a question about why a fast-growing economy is witnessing a weaker currency.Currency strength usually moves in line with economic performance. In simple terms, stronger growth tends to support a stronger currency. But in India’s case, the pattern has not followed that rule in recent years. Since 2018, the rupee has shown a gradual weakening trend almost every year, even though growth numbers have held up relatively strong.Back in 2013, when Narendra Modi was projected as the prime ministerial candidate by the Bharatiya Janata Party (BJP), the falling rupee was a major political talking point. At that time, the exchange rate had crossed the 60-per-dollar level and it was debated in public forums.If the

currency crosses the psychologically important 100 mark, economists say it could create added pressure for policymakers, especially the government and the Reserve Bank of



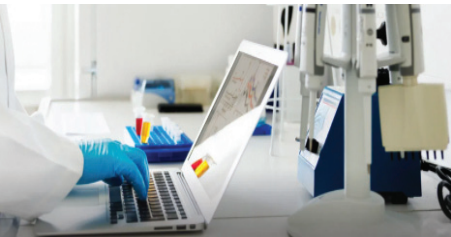
India (RBI).Import costs, oil prices and daily impact
A weaker rupee directly increases India’s import bill. Since the country depends on imports for crude oil, cooking gas, fertilisers and electronics, a fall in the currency makes these essential goods more expensive in rupee terms. This eventually feeds into inflation and raises costs for households.At the same time, there is another side to the story.

Families dependent on remittances benefit when the rupee weakens because they receive more rupees for every dollar sent from abroad. India is among the largest recipients of remittances across the world. In the financial year ending March 2025, overseas Indians sent more than \$135 billion back home.However, this inflow could face disruption due to geopolitical tensions, especially military confrontations in the Middle East that affect Indian workers in Gulf countries.Rising concerns over the currencyThe present weakness of the rupee is also driven by international and domestic factors. Oil prices have risen after attacks on Iran by the United States and Israel. It increased India’s trade deficit. Since the country imports around 90 percent of its crude oil requirement, higher international prices directly increase dollar demand.Foreign investors have also been pulling money out of Indian markets. Reports suggest that around \$23 billion have been withdrawn from Indian equities this year.

Pharma stocks regain health amid geopolitical tension: Gain up to 31% in a month

New Delhi,.(Agency)
Pharma stocks have scripted rare success in the stock market in the past one month despite the dangerous and wide ramifications of the US-Iran tensions and global uncertainties arising thereof. Pharma stocks have performed remarkably and attracted investor attention since many stocks have recorded a strong rally even when the broader was in turmoil. In the past one month, the Nifty Pharma index has risen by about 11% while in the same period the benchmark Nifty 50 index has gone down by about 2.98%.
Gland Pharma records the biggest gains
In the rally of the past month, Gland Pharma has emerged as the top performer. Its shares have surged more than 31% in the past month. Laurus Labs and Biocon also recorded gains of 19.44% and 19.54%. Stocks such as Ajanta Pharma, Cipla, Mankind Pharma, Granules India, Sun Pharmaceutical Industries, and Zydus

Lifesciences have seen gains ranging from 10% to 15%. Some quarterly earnings have beaten market estimates.Q4 results to dollar revenues



Analysts have attributed a few reasons to this surge in some pharmaceutical sector stocks. One, Q4FY26 results have been better than expected. Two, the weakening rupee has actually benefitted some export-oriented pharma companies, whose dollar revenues are raising their bottom lines and revenues. Three, the pharma sector is considered a defensive defensive

sector, which means that demand for medicines and healthcare services remains strong during economic crises or wartime situations. Therefore, many investors are flocking to pharm stocks in a volatile market.Another point to note is that some Indian pharma companies are benefiting from a robust pipeline of specialty drugs and upcoming biologics patents in the US markets, providing long-term growth visibility in highly regulated markets.“Pharma is one sector that has been performing well for quite some time. Over the past one month, we have witnessed strong buying interest in the sector. Most of these companies have reported reasonably well quarterly numbers. Export is one part which is completely benefiting. Depreciating rupee against the dollar is an advantageous position for pharma as well as for industries involved in export-oriented business.

Not Saudi, not US: India's newest major oil supplier may surprise you

Venezuela became India's third-largest crude supplier in May, overtaking Saudi Arabia and the United States. The shift shows how lower prices and regional supply disruptions are reshaping India's crude sourcing.

New Delhi.(Agency)
Venezuela has emerged as India’s third-largest crude oil supplier in May, overtaking traditional heavyweights Saudi Arabia and the United States, as Indian refiners increased purchases of cheaper Venezuelan crude amid ongoing disruptions in global oil markets.According to data from energy cargo tracker Kpler, Venezuela supplied around 417,000 barrels per day (bpd) of crude oil to India so far this month, sharply higher than 283,000 bpd in April. The South American country had supplied

no crude to India during the previous nine months.The jump comes at a time when India is reshuffling its crude oil sourcing strategy due to the ongoing West Asia conflict, disruptions around the Strait of Hormuz and changing global supply dynamics.Only Russia and the United Arab Emirates supplied more crude oil to India than Venezuela in May. WHY INDIA IS BUYING MORE OIL FROM VENEZUELA
The main reason behind the surge is price. Venezuelan crude is currently cheaper than many other global oil grades, making it attractive for Indian refiners dealing with elevated crude prices and geopolitical uncertainty.“Indian buyers have historically shown strong interest in Venezuelan barrels due to their attractive economics and compatibility with complex refining systems,” Nikhil Dubey, Lead Analyst-Refining at Kpler, said, as quoted by The Economic Times (ET).Indian refiners, especially Reliance

Industries, are among the biggest buyers because Venezuela’s heavy and high-sulphur crude suits complex refinery systems such as Reliance’s Jamnagar refinery in Gujarat.Most Indian refiners can process Venezuelan crude only in limited quantities, but Reliance’s advanced refining infrastructure makes it one of the biggest beneficiaries INDIA’S OIL IMPORTS RISE, BUT STILL BELOW PRE-WAR LEVELS
India’s overall crude oil imports rose 8% month-on-month to around 4.9 million barrels per day in May, according to Kpler data.However, imports still remain below



the 5.2 million barrels per day recorded in February, before the Iran war disrupted energy shipments from West Asia. The near closure of the Strait of Hormuz had severely impacted oil shipments from key Middle East suppliers earlier this year. Although some Iraqi crude cargoes resumed this month, volumes remain sharply lower.India received only around 51,000 bpd from Iraq so far in May, compared to nearly 969,000 bpd in February.IRAN SUPPLIES HALTED AGAIN
India had briefly resumed crude imports from Iran in April after the US eased sanctions restrictions earlier this year. That marked the first Iranian oil imports into India in nearly seven years. However, those shipments have once again stopped.No Iranian cargoes have arrived in India this month following the US naval blockade around Iranian ports amid the ongoing conflict.The disruption forced Indian refiners to look for alternative sources, benefiting suppliers such as Venezuela and the UAE.

Bandra slums demolition was decades overdue. But has Railways got the timing wrong?

Western Railway demolished hundreds of houses and shops in Bandra's Garib Nagar after a court-backed clearance drive. A section of people backed the drive as long-overdue for safety and growing infrastructure needs. Others have criticised the timing as the displaced families will have no roof over their head during the monsoon.

New Delhi.(Agency)
"I have never liked the sight of slums right outside Bandra station. Nobody does. The area was filthy, crime was rampant, and it was common to see drug addicts on the foot overbridges despite the presence of the Government Railway Police (GRP). But watching school-going girls in their uniforms sitting on the road, barely metres away from the homes they grew up in, holding on to just a bag of belongings they could save, is a heartbreaking sight," said Devesh Kamble, a software engineer who commutes daily from Bandra East to Kalanagar. As he shared this experience with India Today Digital, bulldozers reduced homes to rubble in Mumbai's Garib Nagar slum outside Bandra station's eastern side. The ongoing demolition drive

by Western Railway in Bandra East has cleared over 400 unauthorised structures, including homes and shops, on railway land hugging the tracks. The Bombay High Court backed the action to reclaim about 5,200-5,300 square metres for railway expansion, including new lines, better connectivity between Bandra Terminus and suburban stations, and support for projects like improved access to the Bandra Kurla Complex (BKC). The land, long encroached upon, holds an estimated value of around Rs 600 crores. Though the anti-encroachment drive and cleanup were long overdue, the reality has two sides to it.

SLUM DWELLERS LEFT WITHOUT A ROOF JUST AHEAD OF MONSOONS
Garib Nagar, one of Mumbai's older and



denser slum pockets, featured multi-storey structures. Many of them were two or three storeys high, built directly beside railway tracks. Residents and commuters have long described these areas as among the filthiest and dingiest in the city, with poor sanitation, waste dumping, safety hazards, and high crime. For decades, they blocked

infrastructure upgrades and posed risks to train operations. Yet these slums housed thousands who form the backbone of Mumbai's workforce — daily wagers, service staff, and essential workers keeping the city running. Many had lived here for 40 years or more. "This slum, inhabited nearly two hundred years ago, now lies abandoned. Residents, along with their wives and children, sat in an open field, carrying household items, watching their homes collapse," social activist and journalist Siraj Noorani said in a post on X. Families pleaded with officials amid the rubble to not demolish the house, or at least let them take their household items out, only for the bulldozers to silence their pleadings. One viral video showed an elderly woman distressed over the rubble,

saying she could not even retrieve a religious scripture from her house. Officials arrived at the site in Garib Nagar on Tuesday (May 19) with heavy earthmovers and bulldozers, police, and RPF personnel, giving little time for residents to salvage belongings. Over 60% of the demolitions happened in a matter of just 48 hours. With thousands displaced right ahead of monsoon, the footage of belongings piled on roads is going viral now. The timing of Western Railway carrying out the eviction has sparked criticism. The southwest monsoon is expected to hit the Kerala coast around May 26 — nearly a week early — and reach Mumbai by early June. With rains just weeks away, displaced families are left without any shelter.

Higher rates, low availability: Protest disrupts commuter mobility in capital

New Delhi.(Agency)
Auto-rickshaw and commercial vehicle unions across Delhi-NCR kicked off their three-day strike on Thursday, citing rising fuel prices, increasing operational costs, and unsustainable commission structures imposed by ride-hailing platforms such as Uber, Ola, and Rapido. The travel across several parts of the capital was apparently disrupted, leaving office-goers and college students struggling to secure rides, particularly during peak hours. Many commuters reported longer wait times, reduced availability of autos and cabs booked via app-based aggregators, and inconsistent fares. "A ride from Chanakyapuri to Satya Niketan cost me Rs 100 today. Usually, even during peak hours, I pay around Rs 70," said Aayushi, a college student in Delhi University's South Campus area. Shivin Bhargava faced a steeper increase. "I paid Rs 160 for an auto to travel from South Campus to Saket, whereas the same route usually costs me about Rs 80," he said.

For others, the issue wasn't just the pricing but availability. "Ever since the protest was announced, getting an auto has become extremely difficult, even for very short distances," said Harsh Malhotra from Faridabad. "The fares are still high despite the shortage, and most drivers are refusing shorter routes altogether." Saba Taherypour from Gurgaon also reported facing similar issues with ride availability and fluctuating prices during the day. Even the Uber and Ola cabs, which were available with much waiting, showed extra prices. From ITO to Mayur Vihar, which generally costs Rs 150-180, the charges on Thursday went up to as high as Rs 200-245.

Transport unions argued that the strike has become necessary due to mounting fuel costs and declining earnings for drivers working through app-based services.

DDA gives 15-day relief to Yamuna Bazaar residents

New Delhi.(Agency)
Two weeks after the Delhi Disaster Management Authority (DDMA) issued an eviction notice to residents of 310 dwellings of Delhi's Yamuna Bazar, the Delhi Development Authority (DDA) has also issued another public notice directing all "unauthorised occupants/encroachers" living along Yamuna Bazaar to vacate the area within 15 days. They also warned that failure to comply could lead to demolition and removal action without further notice.

On Tuesday, the High Court dismissed a plea challenging the eviction notices issued to the families in the Yamuna Bazar area. The DDA notice was issued three days before the HC order, which is on May 15.

Earlier, the DDMA notice which was issued on May 7 gave 15 days of time to the residents, which will be over on May 22. However, with the latest notice from the DDA, the residents have time till May 30.

The notice has been addressed to occupants residing between Ghat No. 2 and Ghat No. 32 near Yamuna Bazaar and concerns land identified as part of the Yamuna floodplain and O-Zone area.

According to the notice, authorities have reported that certain persons are in unauthorised possession of government land falling within the Yamuna floodplain in Revenue Estate Bela. The land has been described as government land under DDA jurisdiction.

Meanwhile, on the ground there is not much panic visible as residents continue to live their lives normally without any signs of packing bags and belongings.

Seven days to submit objections

The notice said that occupants seeking to challenge the action have been given seven days to submit objections or representations before the office. The notice also mentioned that the floodplain area is an ecologically sensitive zone and should remain free of encroachment in accordance with planning provisions and directions issued by courts.

Three children flee home in Gujarat after father takes away mobile phone

New Delhi.(Agency)
According to the complaint, the father had travelled to his native village late last month and had accidentally left his phone at home. During his absence, the children allegedly spent long hours playing games on the device. When he returned, the children's mother expressed concern that the siblings had become excessively dependent on mobile gaming. In an attempt to curb the habit, the father reportedly removed the SIM card from the phone three days before the incident and locked the device inside a cupboard. Police said the restriction angered the children, who then allegedly decided to leave home. The siblings,

who belong to a labourer's family engaged in Surat's textile industry, are also suspected of taking around Rs 15,000 in cash before fleeing.



After discovering the children missing, the family immediately approached the police and filed a complaint. "The complainant informed us that the children spent

most of their time playing mobile games and engaging in similar activities. Upset over this, the father had scolded and counselled them.

The children appear to have taken the matter seriously and left home with some belongings and cash," Police Inspector SD Rathod said.

He added that five police teams had been formed to trace the siblings, with assistance from senior officers and other police units. "Based on CCTV footage and preliminary investigation, we suspect the children may have boarded a train to Mumbai. We have received some positive leads, and teams are actively working at all possible locations," Rathod said.

Fire scare on Air India flight triggers full emergency at Delhi airport

New Delhi.(Agency)
A Delhi-bound Air India flight from Bengaluru triggered a full emergency response at the capital's Indira Gandhi International (IGI) Airport on Thursday night after the pilot reported a suspected smoke-related incident while landing, sources said. The incident involved flight AI2802 operating from Bengaluru to Delhi with 171 passengers onboard. Sources from Air India confirmed to India Today that during the landing procedure, the pilot announced that the engine had caught fire, prompting authorities to declare an emergency at Delhi airport as a precautionary measure.



Despite the scare, the aircraft landed safely, and no injuries were reported. The authorities said that the operations duty manager observed no

pilot also suggested pulling the aircraft off the runway.

In a statement, Air India said it is aware of the incident involving flight AI2802 on May 21, 2026, adding that the aircraft landed safely and there was no harm to passengers or crew.

"We are currently gathering additional information and are working closely with the relevant authorities. Further updates will be shared as more details become available," the airline said.

A full emergency at an airport is usually declared when there is a potential threat to aircraft safety, allowing emergency services including fire and rescue teams to be positioned in advance.

Bhojshala temple dispute reaches SC as Muslim side challenges High Court order

New Delhi.(Agency)
The decades-old dispute over the Bhojshala-Kamal Maula Mosque complex in Madhya Pradesh's Dhar has now reached the Supreme Court, with the Muslim side challenging a recent High Court verdict that recognised the site as a temple dedicated to Goddess Vagdevi Saraswati and barred Friday namaz at the premises. The petition has been filed by Qazi Moinuddin, the mosque's caretaker and one of the intervenors in the case, against the May 15 judgment delivered by the Indore bench of the Madhya Pradesh High Court.

The Intazamiya Committee Kamal Maula Masjid and the All India Muslim Personal Law Board were also among the parties contesting the matter before the High Court. Challenging the verdict before the Supreme Court, the Muslim

side has argued that the High Court ruling runs contrary to archaeological evidence and violates the spirit of the Places of Worship Act, 1991. Anticipating a challenge to the verdict, Hindu parties had already filed a caveat petition in the Supreme Court seeking that no ex parte order be passed without hearing them.

HIGH COURT ORDER

In its landmark ruling, the High Court held that the religious character of the disputed complex was that of Bhojshala, a temple associated with Goddess Saraswati and linked to Parmar ruler Raja Bhoj, who is credited with turning Dhar into a centre of Sanskrit learning.

A division bench of Justice Vijay Kumar Shukla and Justice Alok Awasthi

observed that historical records, archaeological material and literary evidence supported the Hindu claim



over the site. The High Court said the available materials established the existence of a temple dedicated to Goddess Vagdevi Saraswati at Dhar and noted continuity of Hindu worship at the

site overtime.

The High Court also quashed the Archaeological Survey of India's 2003 arrangement that allowed Hindus to perform puja on Tuesdays and Muslims to offer namaz on Fridays at the protected monument. With the order being struck down, the weekly Friday prayers by the Muslim community at the complex stand discontinued.

"The historical literature of the place establishes it as a centre of Sanskrit learning associated with Raja Bhoj. It indicates the existence of a temple dedicated to Goddess Vagdevi Saraswati at Dhar. Therefore, the religious character of the area is held to be Bhojshala with temple of Goddess Vagdevi Saraswati," the court said in its ruling.

Why ED is chasing Kolkata cop as criminal links to TMC's 'golden boy' emerge

After the BJP's election win, the ED has launched an aggressive crackdown on criminal syndicates that the party claims are in cahoots with the TMC. At the heart of the probe lies a startling nexus between a senior Kolkata cop and a notorious criminal believed to be close to TMC.

New Delhi.(Agency)

On Friday, even before dawn had fully broken, the Enforcement Directorate (ED) embarked on, perhaps, its most sweeping operations in Bengal in recent years. In fact, after the BJP's election win, central agencies have launched an aggressive crackdown on criminal syndicates and extortion gangs that the party claims were in cahoots with the TMC. At the heart of the probe lies a startling nexus - a senior Kolkata Police officer who was previously in charge of the area where Mamata Banerjee resides and notorious strongman Sona Pappu, often described as the TMC's 'golden boy'.

The ED believes Kolkata DCP Shantanu Sinha Biswas and Pappu, alias Biswajit Poddar, were central figures in an alleged racket involving land grabbing, extortion, illegal construction, and hawala dealings. Biswas and Pappu, who was on the run for over three months, were arrested by the ED last week, triggering a major stir in Bengal. It has led to speculation that the probe could lead to more high-profile names and explosive revelations.

ED CRACKDOWN ON SYNDICATES

On Friday, ED teams fanned out across nine locations in Kolkata and Murshidabad linked to Biswas and Pappu. One ED team landed at the former DCP's luxurious ancestral home in Murshidabad's Kandi town. However, the gates were locked. Drama ensued as the ED officers broke open the gates and barged in. Stunned locals watched in silence as the raid unfolded.

The image was a far cry from when ED officers were allegedly attacked by TMC goons during a raid at the residence of former TMC leader and strongman Sheikh Shahjahan in Sandeshkhali. On Friday, the ED officers spoke to locals outside the premises before breaking in. Biswas's sister, Gauri Sinha Biswas, who is the vice-chairperson of Kandi Municipality, was not present at the residence.

NEWS BOX

Oil market risks 'red zone' by summer, IEA chief warns

LONDON. (Agency)
The world oil market risks entering a "red zone" by the upcoming summer season should there be no progress on ending the West Asia war, the head of the International Energy Agency warned Thursday.
"We may be entering the red zone (on supplies) in July or August if we don't see that there are some improvements in the (war) situation," Fatih Birol said at the Chatham House think tank in London.
Iran has effectively halted tanker traffic through the Strait of Hormuz in retaliation for US and Israeli strikes launched in late February, choking off oil and gas traffic and sending prices soaring.
While a surplus of oil in the market before the war has helped absorb the energy shock, "stocks are eroding", Birol said.He warned that it will take "a lot of time" for production and refining capacity to return to pre-war levels.Birol previously said that commercial oil stocks are falling "very fast", even with the release of strategic reserves by governments worldwide.
The IEA has coordinated the release of 426 million barrels from emergency stocks by its 32 member countries, and said this month that around 164 million barrels have already been drawn.A ceasefire on April 8 halted the war, but negotiation efforts have so far failed to yield a lasting peace agreement, weighing on the world economy.

Farmers Turn to Human Urine After Fertiliser Crunch From Iran War

world.(Agency)
After the Iran war disrupted supplies of conventional nitrogen fertilizers, the English farmer began scouring the Yorkshire countryside for substitutes to keep his crops growing. That led Mills to the poultry shed of a relative's friend, whose chicken manure is suddenly so sought after that he now has a long list of buyers."Everyone is doing the same, looking for alternatives," said Mills, who harvests wheat, barley and oats on a farm dotted with sheep.
Farmers worldwide are under pressure. About a third of traded urea, a widely used nitrogen fertilizer, comes from the Gulf region. With the Strait of Hormuz effectively shut, prices have jumped to multi-year highs. That's forcing growers to improvise ahead of the fall planting season or risk lower yields, profit losses and disruptions to global food supply.
Some are turning to age-old solutions like manure. Others are experimenting with newer technologies. These range from waste-based inputs, including materials like ground almond shells, to microbial products designed to boost plant growth and reduce reliance on chemical fertilizers.
"The war situation is, sadly, a good thing for us," said Francois Gerard of French startup Toopi Organics, which converts human urine collected from schools and festivals into a bacteria feed that helps plants grow. Since late February, sales have jumped about a quarter, he said, with prices holding steady thanks to abundant supply. With no end in sight to rival US and Iranian blockades in Hormuz, fertilizer disruptions are expected to persist. A prolonged conflict could mean weaker harvests and higher grocery prices. The United Nations has warned that an additional 45 million people may face acute food insecurity.Because farmers plan months ahead, the effects risk rippling into yields as far out as 2027, according to the UN's Food and Agriculture Organization. The World Bank expects fertilizer prices to rise by nearly a third this year, pushing affordability to its worst level since 2022, when Russia invaded Ukraine.

A 'Band Of Brothers' Is Running Iran With Mojtaba Khamenei: Report

Tehran.(Agency)
When Ali Khamenei, Iran's supreme leader for 37 years, was assassinated in an Israeli strike on February 28, it created a vacuum at the top and changed the power corridors of Tehran. His son, Mojtaba Khamenei, was appointed his successor, but reports have suggested that the 56-year-old cleric does not wield the same level of influence as his father did. Instead, a small, elite band of men in senior positions, most of whom are current or former senior Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) commanders, are guiding decision-making in Iran, according to a New York Times (NYT) report.
"Senior Iranian officials maintain that all key matters are run by the 56-year-old heir. Decision making, however, extends beyond one man," the report said, adding that a "hardened band of brothers" whose "seminal experience was the brutal, eight-year war between Iran and Iraq that began in 1980."
ALSO READ: Iran Executes Two Men Over Armed Rebellion Charges, Links To 'Separatists'
"The Band Of Brotherhood'Founded in 1979 to protect the Islamic revolution and its leader, the Guards promoted some of these commanders to the rank of general while they were still in their late 20s or early 30s. The West's support for Iraq in the war convinced Tehran that Iran had to forge its own way, no matter the cost. After the war with Iraq was over, these commanders went on to control intelligence or security services. Experts point out that their shared backgrounds, careers and ideological outlook are the reasons why neither the war nor the collapse of the government and assassinations of around 50 top political and military leaders could paralyse Tehran. How these leaders operate and share power remains largely opaque. Some have been out of the limelight long before the war started, and now remain hidden out of fear of being targeted. But now, they have joined forces and become "a brotherhood running the country," Saeid Golkar, a Guards expert who is a political science professor at the University of Tennessee at Chattanooga, told NYT.

Ebola case confirmed in rebel-held Congo's South Kivu area

DR CONGO. (Agency)
An Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo has spread to eastern South Kivu province in an area under the control of the Rwanda-backed M23 militia, the group's spokesman said Thursday, heightening fears of the deadly disease's growing reach.Efforts to get a grip on the latest outbreak of the highly contagious haemorrhagic fever, which the World Health Organization has declared an international emergency, have been hampered by the DRC's long-running conflicts, including between the Congolese army and the M23.Having seized swathes of land in the mineral-rich east with Rwanda's help, the M23 has installed a parallel administration in areas under its control.But the armed group has never had to manage the response to a serious epidemic of a disease like Ebola, which has killed more than 15,000 people in Africa in the past half-century.The virus is spected to have claimed 160 lives out of nearly 671 probable cases, according to figures

published by the National Institute fr Public Health (INSP) on Thursday.There are 64 confirmed Ebola cases and six confirmed deaths, INSP said.Tests "confirm a new positive case" in Kabare territory in South Kivu, M23 spokesman Lawrence Kanyuka said in a statement.Parts of South Kivu, including the provincial capital Bukavu, fell to the M23 in February 2025 after fierce clashes.The case involved a "person coming from Kisangani", a major city in the eastern Tshopo province, where no Ebola infections from the current outbreak have so far been recorded.Congolese authorities, in a statement on Thursday, reported two cases identified in South Kivu province -- one suspected case and one confirmed.Riot at hospitalThe outbreak's epicentre is in northeastern Ituri province, with many cases in hard-to-access areas plagued by the Congolese east's litany of armed groups and where measures to respond to the crisis have been slow to get off the ground."We have no sanitary facilities at all, not even a handwashing

station, for 16,000 displaced people," said Desire Grodya, an official at a site for displaced people in Kigonze, on the outskirts of Bunia, Ituri's provincial capital.



"We're really crammed in here; it's total overcrowding... If the outbreak starts on the site, it will be catastrophic," he warned.
On Thursday, a brief riot erupted at the hospital in Rwampara, one of the outbreak's focal points located about 12 kilometres (seven miles) from Bunia. Young people who "wanted to retrieve the body" of a deceased patient "entered the hospital and burned down the two isolation tents", a hospital official told AFP.A

healthcare worker was also injured by stone-throwing before law enforcement intervened, the official said.The isolation tents had only just been put up at the hospital.Cases have also been recorded in North Kivu province and neighbouring Uganda, where one person has died.Split by front lines
Both North and South Kivu are split in two by the front lines dividing the Congolese army from the M23 armed group and its Rwandan allies.No vaccine or clinical treatment exists for the Bundibugyo strain of the Ebola virus responsible for the current epidemic."Every passenge who arrives here, whether at the airport entry point or elsewhere, is subject to a temperature check," said Aime Prospere, head of border hygiene at Bunia airport, in a statement.Tons of equipment have been delivered at the airport by the WHO and NGOs since Monday.In the city "we're not allowed to carry two people on the same motorcycle". Paulin Kibondo, a motorcycle taxi driver, said.

US pins hopes on mediator Pakistan in push to end Iran war

TEHRAN.(Agency)
TUS Secretary of State Marco Rubio voiced hope of progress on ending the war with Iran, as he looked to Pakistani mediators to help advance efforts to strike an agreement.
Previous comments by President Donald Trump had suggested weeks of stop-start negotiations to strike a permanent end to the war were teetering on the "borderline" between a deal and renewed attacks."I believe the Pakistanis will be travelling to Tehran today. So hopefully that'll advance this further," Rubio told reporters on Thursday.A ceasefire on April 8 halted the war launched weeks earlier by the United States and Israel, but negotiation efforts, including historic face to face talks hosted in Islamabad have so far failed to yield a lasting agreement.Pakistan's interior minister Mohsin Naqvi, who is widely considered close to Pakistan's powerful army chief Asim Munir, visited Iran for the second time in a week on Wednesday.Iranian media,



comment from Pakistan authorities about any travel plan for the army chief. Beijing did however, announce that Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif will travel on Saturday to China, which has also been involved in mediation efforts to end the war.BorderlineThough open warfare and strikes across the Gulf have reduced, the impasse continues to

weigh on the world economy.In April, Pakistan hosted the only direct negotiations, which Munir helped mediate, between US and Iranian officials to take place since February 28, when the war began.But the talks ultimately failed, with Tehran accusing Washington of making "excessive demands".Since then, the two sides have exchanged multiple proposals, with the threat of renewed conflict looming all along."It's right on the borderline, believe me," Trump told reporters Wednesday. "If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go."He said a deal could come "very quickly" or "in a few days", but warned Tehran would have to provide "100 percent good answers".Rubio also criticised NATO allies for their refusal to help in the war against Iran."He's not asking them to commit troops. He's not asking them to send their fighter jets in. But they refuse to do anything," he said."We were very upset about that."

Gunmen open fire in two separate attacks in Honduras, killing at least 25 people

TEGUCIGALPA.(Agency)
Gunmen opened fire in two separate attacks Thursday on the Honduran coast, killing at least 25 people, including six police officers, authorities said.The first incident took place at a plantation in the municipality of Trujillo in northern Honduras, where at least 19 workers were shot and killed, according to Public Prosecutor's Office spokesperson Yuri Mora.The resource-rich region has been the site of a decades-long agrarian conflict.The Inter-American Commission on Human Rights has previously issued precautionary measures to some activists in the region who have been threatened, surveilled and intimidated for their work defending the environment and land rights.The 2024 killing of environmental leader Juan López highlighted the dangers of defending

natural resources in this highly militarised area of Honduras. The Central American nation regularly ranks as one of the most dangerous for environmentalists, with five killed in 2024 and 18 the year before, according to nongovernmental organisation Global WitnessThree people were recently arrested for masterminding López's killing, providing a rare glimpse of justice in a country with high rates of impunity.In the second attack, assailants opened fire on police in the municipality of Omoa in the Cortes department near the Guatemalan border,killing six officers, including a senior officer, police said.The officers were assigned to an anti-gang mission and were attacked while traveling to Omoa from the capital, Tegucigalpa, police said.National Police spokesperson Edgardo Barahona said earlier

Thursday that determining the death toll in Trujillo was complicated partly because relatives of the victims have removed bodies of their loved ones. Investigators have been sent to the scene, he said.The National Police and armed forces will respond to both of the areas where attacks took place, and teams including forensic specialists and prosecutors will be formed to investigate, the Security Ministry said.
Honduras has struggled with high rates of crime linked to gangs and the transnational drug trade, although its homicide rate has decreased significantly in recent years since a 2011 peak of 83 murders per 100,000 residents, according to the World Bank.International human rights organisations have criticised Honduras for its militarised approach to fighting crime, which they say has led to human rights abuses including torture.

Trump says he is sending 5,000 more troops to Poland, stirring confusion about US presence in Europe

The Trump administration had earlier said it was reducing levels in Europe by about 5,000 troops, and US officials confirmed about 4,000 service members were no longer deploying to Poland.

WASHINGTON.(Agency)
President Donald Trump on Thursday said the US will send an additional 5,000 troops to Poland, stirring confusion following weeks of changing statements from Trump and his administration about reducing — not increasing — the American military footprint in Europe.The Trump administration has said it was reducing levels in Europe by about 5,000 troops, and US officials confirmed about 4,000 service members were no longer deploying to Poland. Trump's social media

announcement raises more uncertainty for European allies that have been blindsided by the changes as the administration has complained about NATO members not shouldering enough of the burden of their own defense and failing to do more to support the Iran war."Based on the successful Election of the now President of Poland, Karol Nawrocki, who I was proud to endorse, and our relationship with him, I am pleased to announce that the United States will be sending an additional 5,000 Troops to Poland," Trump said on Truth Social.Trump and the Pentagon have said in recent weeks that they were drawing down at least 5,000 troops in Germany after Chancellor Friedrich Merz said the US was being "humiliated" by the Iranian leadership and criticized what he called a lack of strategy in the war.

Trump then told reporters at the beginning of the month that the US would be "cutting a lot further than 5,000."As of last week, some 4,000 troops from the Army's 2nd Armored Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division were no longer en route to Poland. The Associated Press reported

that the canceled deployment was part of an effort to comply with Trump's order to



reduce the number of troops in Europe. A deployment to Germany of personnel trained to fire long-range missiles also was halted.Democratic and Republican lawmakers alike criticised the reductions as sending the wrong signal both to allies and Russian President Vladimir Putin during the 4-year-old war in Ukraine.Republican Rep. Don Bacon of Nebraska said during a congressional hearing that he spoke with Polish officials and they were "blindsided." He called the decision "reprehensible" and said it was "an embarrassment to our country what we

just did to Poland."Chief Pentagon spokesman Sean Parnell said Tuesday that it was "a temporary delay" of the deployment of US forces to Poland, which he called a "model US ally." He said it was a result of the US reducing the number of brigade combat teams assigned to Europe from four to three and indicated the Pentagon still needed to decide which troops to station where.It was not clear whether that meant the brigade would resume its deployment to Poland, if additional troops on top of that rotational deployment could be added, or whether there would still be a drawdown of US troops in Europe but from a different country. The Pentagon referred requests for comment to the White House, which did not immediately respond to messages seeking clarity.Defense Secretary Pete Hegseth and Defense Undersecretary Elbridge Colby both spoke with with their Polish counterparts this week. Polish Prime Minister Donald Tusk had said Wednesday that he was happy to hear "Washington's declaration that Poland will be treated as it deserves.

NEWS BOX

Drums and tears: Cristiano Ronaldo celebrates Saudi league title, X post goes viral

CHENNAI. (Agency)

They said he went to the desert to retire. They said the hunger would fade, buried under the weight of a 200-million-euro contract and the twilight of a legendary career. But on a sweltering Thursday night at Al-Awwal Park, as the final whistle blew to confirm Al-Nassr as the Saudi Pro League champions, Cristiano Ronaldo proved once again that his obsession with winning defies both time and critics.At 41 years old, a man who has conquered Manchester, Madrid, and Turin stood on a football pitch in Riyadh and wept like a teenager winning his very first medal.

Cristiano Ronaldo lifts the 2025/26 #RoshnSaudiLeague trophy pic.twitter.com/gjFKcDJ4vd— Roshn Saudi League (@SPL_EN) May 21, 2026

They stakes could not have been higher on the final night of the season. Al-Nassr held a razor-thin advantage, knowing anything less



than a victory could hand the crown to their relentless arch-rivals, Al-Hilal. The atmosphere inside the stadium was electric, a sea of yellow and blue roaring for a domestic title that had eluded the club since 2019. Early goals from Sadio Man and Kingsley Coman put Al-Nassr in control, but a tense penalty from Damac brought the score to 2-1, stretching the nerves of everyone in the arena to a breaking point.Then came the 62nd minute, the moment the script belonged to Ronaldo. Standing over a free-kick twenty-five yards out, he took his trademark deep breath, his eyes locked onto the top corner. With a devastating blend of power and dip, he struck the ball. It bypassed a desperate wall and a forest of legs, rocketing into the far corner of the net. The stadium exploded. It was vintage, peak Ronaldo, delivered precisely when his team needed a saviour. Nine minutes from time, he put the final exclamation point on the season, smashing home a sharp cut-back from the edge of the six-yard box to make it 4-1

Illish finally beats Chingri again as East Bengal end 22 years of Bangal pain

After 22 years of inherited heartbreak, corporate chaos, and near-misses, East Bengal's dramatic ISL title triumph has revived a sleeping giant. The moshal burns bright again; Kolkata's red-and-gold half has finally reclaimed its soul.

LONDON. (Agency)

When a child is born in a Bengali household, one of the earliest loyalty tests that he or she needs to take is not political, not cultural, not even cinematic. It is football.Whether they will grow up eating Illish in red-and-gold or Chingri in green-and-maroon, whether their heart will belong to East Bengal or Mohun Bagan.A grandfather still emotionally talks about PK Banerjee, a father remembers Bhaichung Bhutia carrying East Bengal on his shoulders, and now a son debates Cleiton Silva versus Dimitrios Petratos on Instagram

Reels and X threads.But for the last 22 years, that emotion has often hurt far more for East Bengal supporters.

The rivalry itself never lost its intensity, but slowly the balance of success drifted heavily towards the green-and-maroon side of the city. Mohun Bagan kept collecting league titles, ISL finals and continental nights while East Bengal fans were left surviving mostly on memories, nostalgia and endless reminders of “kobe abar champion hobe?” That is why on May 21, 2026, when the final whistle blew at Kishore Bharati Krirangan after East Bengal's dramatic 2-1 win over Inter Kashi, years of pain disappeared in seconds.

Fans flooded onto the pitch almost immediately. Oscar Bruzon and Youssef Ezzejari were lifted onto supporters' shoulders and tossed into the Kolkata night as moshals lit up again.Social media instantly became a flood of red-and-gold emotion. One East Bengal supporter uploaded a video looking at the sky saying, “Baba, amra abar champion holam” — “Father, we are champions again.” His father

had passed away years ago without seeing East Bengal win another national league title after the 2003-04 National Football League



triumph under Subhash Bhowmick.Another elderly supporter, probably in his seventies, stood outside the stadium crying uncontrollably while saying, “Jibon-e shob dekhlam, kintu eta aar dekhbo bhabini” — “I have seen everything in life, but I never thought I would see this again.” That is what these 22 years really were. An entire generation growing older while carrying football heartbreak almost like inherited

trauma.Kids who last saw East Bengal as champions in 2004 are now full-grown adults. Some finished school, college, jobs, marriages and even became parents before finally watching East Bengal lift another major national league title again.Indian football itself moved through entire eras during this wait, from the Bhaichung Bhutia-Mike Okoro days under the chest-thumping intensity of Subhash Bhowmick to an ISL generation raised on transfer rumours, meme pages and yearly derby meltdowns online.

Indian football itself completely changed during that period. The National Football League disappeared and the I-League arrived. Then came the chaos and glamour of the ISL era.Yet somehow, East Bengal's pain survived every single era.

Trevor Morgan's side gave supporters genuine hope during those early 2010s years with magical AFC Cup nights and aggressive football that made fans dream again. Then came the near misses in 2010-11 and 2013-14 before the particularly painful 2014-15 collapse when Mohun Bagan edged them to the title.

Season ends, enigma endures: CSK deliver final word on MS Dhoni's IPL future

New Delhi. (Agency)

The great theatre of Indian cricket rolled on at the Narendra Modi Stadium, but as the dust settled on Chennai Super Kings' crushing 89-run defeat to Gujarat Titans, the post-match conversation inevitably pivoted away from the scorecard. CSK were officially knocked out of the IPL 2026 playoffs race, and with their campaign brought to a grinding halt, the single most enduring question in modern sport resurfaced: What happens next to MS Dhoni?For months, the franchise had operated under a veil of intense secrecy. Dhoni did not play a single fixture this season, nor did he travel with the team for most of their away games, remaining a looming, legendary shadow over the transition era. Minutes after a dejected skipper Rituraj Gaikwad told reporters that the world would “know next year,” it was bowling coach Eric Simons who stepped into the press room to provide the most candid, insightful update yet on the enigma of No. 7.When asked point-blank about whether this was the definitive end of the road for Dhoni, Simons couldn't help but chuckle at the predictability of the

inquiry.Are you seriously asking me that question?” Simons smiled.

"Honestly, he has hit the ball so well. He had a leg injury which made it very difficult for him to run. So that's why he couldn't play. But, in terms of hitting the ball in the nets, he



is hitting it as well as I have ever seen him hit it."Simons' words shed crucial light on Dhoni's mindset: the desire to compete was fully intact, and he was actively priming himself to take the field, but his body simply refused to cooperate. To make matters worse, a fresh thumb injury put an end to any late-season cameos. Dhoni didn't even

travel to Ahmedabad for this final fixture, having already flown back to Ranchi to nurse the blow. Even earlier, during CSK's emotional lap of honour to tribute the fans at Chepauk, eagle-eyed observers noticed his thumb heavily taped.

IT WILL BE DHONI'S CALL

Yet, Simons made it clear that while physical setbacks currently dictate terms, the final decision remains entirely in the hands of the mastermind himself."But, I keep saying this. MS will know and he will only make the decision about when he is ready," Simons explained. "If he knows it is not right, he won't play. But, if he feels it's right, he will. He will make a decision in the best interest of the team and not for himself as an individual."That selfless

approach has defined Dhoni's entire career. Even in a purely dugout-bound, net-bound avatar, his value to a transitioning Chennai side remains immeasurable."It would be great to have him playing," Simons admitted. "It has been great having him around the unit and have the opportunity to tap into all the knowledge and calmness."

IPL Play of the Day: Ahmedabad rings with Suii-raj as the Powerplay King rules



New Delhi. (Agency)

For six balls, Ruturaj Gaikwad made Mohammed Siraj look ordinary. Two towering sixes, a crisp boundary and 14 runs flowed freely as the CSK skipper threatened to turn Ahmedabad into his own stage. But cricket, like theatre, often saves its loudest moment for the perfect cue, and Siraj delivered it on the seventh ball.

The stumps were shattered, the crowd erupted and out came the now-familiar Cristiano Ronaldo-inspired ‘Suuii’ celebration as Siraj roared across the Narendra Modi Stadium on Thursday, May 21. In that instant, the momentum, the chase and perhaps Chennai Super Kings’ entire IPL 2026 campaign came crashing down.Siraj’s blistering new-ball spell, which had already begun with the first-ball dismissal of the dangerous Sanju Samson, tore through CSK’s top order and became the defining act in Gujarat Titans’ crushing 89-run victory.“On a red-soil pitch, I would always try to get Sanju driving,” Siraj said after the game, wearing an exuberant smile on his face.

Removing Urvil Patel for a two-ball duck was the knockout punch, as CSK saw a disastrous end to their powerplay (58/4). And suddenly, a chase of 230 had become a survival mission for CSK, who never truly recovered from the early collapse.What made Siraj’s spell even more remarkable was the nature of the surface and the conditions earlier in the evening. During Gujarat Titans’ innings, Chennai’s bowlers had struggled to create any sort of pressure. Sai Sudharsan and Shubman Gill had dominated proceedings with a breathtaking opening stand of 125 runs from just 74 deliveries, dismantling the CSK attack with calculated aggression and elegant stroke play.At no point during the first innings did the pitch appear difficult for batting. The ball came on nicely, the boundaries flowed and Gujarat’s top order dictated terms from the outset. Yet Siraj somehow extracted movement, bounce and uncertainty with the new ball, exposing the difference high-quality fast bowling can make even on batting-friendly surfaces

RCB vs SRH preview: Top 2 out of grasp, SRH hope to dent RCB's confidence in Hyderabad

RCB vs SRH Preview: Defending champions RCB and SRH will play their final league-stage game in the IPL 2026. RCB are firmly placed at No.1 and SRH are unlikely to make it to the top 2 places due to their NRR deficit. So what's there to play for?

Hyderabad. (Agency)

Royal Challengers Bengaluru and Sunrisers Hyderabad started IPL 2026 with different pressures hanging over them, but both now find themselves exactly where they hoped to be before a ball was bowled. In the playoffs, carrying momentum, belief and the feeling that this could still become their

season.When RCB walked into the tournament as defending champions, scrutiny was inevitable. Winning a title changes everything around a franchise. Every performance is judged differently, every flaw dissected more closely. The challenge was no longer about becoming champions. It was about proving last season was not a fleeting high.For SRH, the pressure came from another direction. Over the last few years, Hyderabad had built one of the most explosive squads in the league, yet they often struggled to sustain rhythm when it mattered most. There were flashes of dominance mixed with stretches of frustration. This season carried the sense that the team finally needed to turn promise into authority.On Friday at the Rajiv Gandhi International Stadium, the two sides meet in their final league-stage fixture. What once promised to be a thrilling finish in the race for the top two has now become largely a formality, because SRH are highly unlikely

to break into those spots due to the massive net run rate gap.The situation changed after Gujarat Titans obliterated Chennai Super Kings by 89 runs a day earlier at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. So, what is left to play for?

RCB HAVE FIRM GRIP ON TOP 2

RCB currently sit at the top of the table with 18 points and the best net run rate in the competition. Another victory would secure a first-place finish and hand them two chances to reach the final, an advantage every team

desperately wants at this stage of the tournament.The strongest feature of Bengaluru's campaign has been the composure with which they have handled pressure. There have been very few off days, no extended slump and hardly any visible panic during difficult moments. Rajat Patidar has captained with calm assurance, creating an environment where experienced names and younger players have thrived together.At the centre of it all has been Virat Kohli. There is something almost expected now about Kohli producing another big IPL season, but familiarity should not take away from the level he continues to maintain. His 542 runs have once again given RCB strong foundations, whether in steep run chases or on slower surfaces where patience mattered as much as aggression.Devdutt Padikkal has looked far more settled this season and has complemented Kohli beautifully at the top. Patidar has brought stability.





Tejasswi Prakash

Defends Karan Kundrra, Addresses Cheating Allegations: 'I Do Not Care...'

Tejasswi Prakash has defended Karan Kundrra. In the recent episode of Desi Bling, the actress was asked about her beau's past relationship, presumably with Anusha Dandekar. Karan and Anusha dated for over three years before parting ways in 2020, following which the former was accused of cheating on the VJ-actress. Tejasswi addressed the same on Desi Bling and said, "We all have our pasts. Somebody's past is out there in public. If he has cheated or not, which again, we don't know, because he has told me. He thought, 'I don't care if the world knows, you need to know the real thing'," as quoted by .

What Happened Between Karan And Anusha?Karan and Anusha dated for three years before they announced their breakup in 2020. They had even co-hosted the reality show MTV Love School.

In September 2021, Anusha held an 'Ask Me Anything' session on Instagram when a user asked her: "Please, I want to know the direct reason for y o u r break-up if you can tell it." To this, the actress replied: "We deserve more honesty, love and happiness...and it starts with self-love. So, I chose me. That's it."

Later, Karan also shared his side of the story while speaking to ETimes, "I have remained silent out of respect for the relationship and I would like to keep it that way. At this point, I am also thinking about two families. I, too, can turn around and say a lot of things, but that's not me. What she shared was her perspective."

After breakup with Anusha, Karan fell in love with Tejasswi Prakash. Their love story is not a secret. They first met while participating in the reality show Bigg Boss. During their time on the show, their chemistry quickly became one of the most talked-about aspects of the season. After the show ended, the couple confirmed that their bond continued outside the house. They began appearing together at public events, vacations and social media posts. Over time, their pairing earned a loyal fanbase, often referred to as "TejRan". Karan and Tejasswi have now been together for nearly five years. Recently, Karan also proposed to Tejasswi on Desi Bling.



Kusha Kapila Says 'Actors Are Right' To Question Influencers Getting Films 'Because Of Followers'



Kusha Kapila's shift from influencing to acting reflects a larger change in the Indian entertainment industry, where digital creators are increasingly crossing over into mainstream cinema and OTT storytelling. As certain studios continue prioritising internet-savvy audiences, influencers with built-in fan bases have become attractive casting choices.

However, Bollywood actors have often called out this practice, saying that casting a role based on followers is a disservice to the craft. Kusha Kapila reflected on this in a chat with Hindustan Times and said, "I feel actors are right to feel that if the hiring is only happening because of followers. They are right to feel that because they have studied for it. They are the ones who should be leading and fronting projects. 100%"

However, Kusha says that this argument cannot be applied to creators who are working hard to hone their skills. She said, "If a creator is taking the time out, putting in the effort, going back to school, learning, workshoping, things get different... For that matter, look at somebody like Bhuvan Bam..."content, and there is proof of concept. If you are taking out the time, and if one is really putting in the work (things are different... Take the time. It's not like you have to prove yourself in just five. An actor can come from anywhere," added Kusha. Asked if she is recognised more as an actor or a social media influencer, Kusha Kapila said, "So, many people definitely recognise me through my projects."

"I started my career with Netflix with Ghost Stories... I am on a very nicely paced journey. I feel like whenever a bigger opportunity presents itself, I want to be ready for it. I don't want to be like I'm less. I want to be like 'I am ready. I feel after Maamla Legal Hai season 2, I would be ready, and would be like 'bring it on','" Kusha shared. She continued, "It is important to pace yourself for a big opportunity rather than get it at a time where you won't be able to do justice to it. I am liking the pace of how things are going. I'm loving it. Bahut maza aa raha hai (I have a lot of fun)."

'Zor Se Sorry Bolo': Paparazzi Apologise To Salman Khan After Hospital Row, Actor Forgives Them



After Bollywood superstar Salman Khan's public display of anger both online and in real life, the paparazzi tendered an apology to the superstar at an event in the city on Wednesday. As the actor walked into the success party of 'Raja Shivaji', he was swarmed by the paparazzi, who immediately apologised for their intrusive behaviour on Tuesday. The paparazzi were heard saying, "sorry" relentlessly as the actor walked in and greeted his friends from the industry. Hearing the commotion, the actor leaned forward, and gestured the paparazzi asking what happened. As he heard their apology, Salman told them it's alright in gesture.

Earlier, the actor had called out the paparazzi after being extremely miffed for creating a ruckus during his hospital visit and invasion of privacy. While the actor expressed his angst, netizens seemed confused by the captions put up by the superstar.

Salman took to his social media account in the wee hours of Wednesday morning and expressed his utter disappointment in the behaviour of paparazzi. He wrote, "If I see any press at a hospital enjoying my pain. The press that I have stood for interacted with, took care to make sure that they also earn their bread and butter. But if they wanna make money from my losses, keep quiet, don't enjoy. bhai bhai matrabhumi picture ki maaa ki aankh, pic imp hai ya life (sic)".

"Aise main sau jala doonga. Bhai k ek bhai k dukh par agli baar try kar lena mere sath. Buss try kar lena Jab bhi tumhara koi hospital mai hoga kya mai aisa react karoonga?", he added. In his final post, Salman warned, "Saath saal ka ho gaya hoon lekin ladna nahiin bhoola yeh yaad rakh lena, jail mein dalo ge haaa haaa".

The posts quickly grabbed attention online, with fans and celebrities flooding the comments section with support. A certain section of netizens seemed confused by the captions, and worried for the actor.



Kiara Advani

Shares In-Flight Glimpse Of Daughter Saraayah Ahead Of Vacation With Sidharth Malhotra

Kiara Advani and Sidharth Malhotra were recently spotted at Mumbai airport as they headed out for a family vacation. The celebrity couple caught the attention of fans and paparazzi with their stylish yet relaxed airport appearance. However, what truly melted hearts was Kiara's adorable glimpse of their daughter, Saraayah. Ahead of boarding the flight, Kiara shared a sweet candid moment from inside the aircraft. Taking to her Instagram stories, Kiara Advani shared a photo which shows daughter Saraayah's hand and a toy on flight's window. The actress has not written much as the caption. She has only added heart emojis.

Recently, Kiara was trolled for her remark during a podcast. Kiara said that she wouldn't want her daughter to feel like she can only date one person and has to marry that same person. The actress said that she wants Saraayah to have a full life, and Kiara would support her even if her daughter didn't want to get married.

Recently, Kiara Advani said on Raj Shamani's podcast. "I would want her to see a very full life. I don't want her to feel like she has to only date one person or she has to... Like, there's no restriction of if you want to get married, get married and if you don't want to get married, don't get married..." Kiara said that everyone she dated, she thought she was going to marry them.

She said, "Life doesn't turn out like that. Thank god it didn't turn out like that because I'm very happy with who god chose as my eventual life partner (Sidharth Malhotra). But all those relations that you have in your life growing up,

they all teach you something.

